THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I am satisfied that this is not a Money Bill...(Interruptions)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Have you got the recommendation of the President?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is not necessary...(Interruptions)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It is a very important issue. You cannot give your ruling like this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is not necessary now. It is only necessary at the time of consideration. So I will ask the Minister to introduce the Bill.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Has the President's recommendation been obtained or not?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is not received at this stage. I am satisfied...(*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Let me ask the Minister...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I should give my ruling and not the Minister and I will have to be satisfied.

SHRI P. A. SANGMA: The President's recommendation is not required because it is not a Money Bill. Where is the question of having the President's recommendation?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now the Minister to move the Bill.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I introduce the Bill.

THE Jammu and Kashmir State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1992

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Jammu and Kashmir to make laws as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The House is aware that the Proclamation dated 18-7-1990 made by the President under article 356 of the Constitution in relation to the State of Jammu and Kashmir, inter alia, provides that the power of the State Legislature shall be exercisable by or under the authority of Parliament. Under article 357(1)(a) of the Constitution, it is permissible for Parliament to confer on the President the power of the Legislature of the State to make laws and to authorise him to delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the power so conferred to any other authority specified by him in that behalf. There are a number of legislative proposals pertaining to Jammu and Kashmir which are required to be re-enacted before 18-7-1992. In view of the otherwise busy schedule of business of the two Houses, it may not be possible for Parliament to deal with various legislative measures that may be necessary in respect of Jammu and Kashmir. The Bill, therefore, seek to confer on the President the power of the State Legislature to make laws in respect of

the State. It has been the normal practice to undertake such legislation in relation to the State under President's rule and the present Bill is on the usual lines. Provision has been made in the Bill for the Constitution of Consultative Committee, consisting of 15 Members of Parliament, (10 Members from the Lok Sabha and 5 Members from the Rajya Sabha) in this regard. Provision has also been made to empower Parliament to direct modifications in the law made by the President, if considered necessary.

I request the hon. House to approve the legislative proposal before it.

The question was proposed.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): What is the total number of such Bills?

SHRI M. M. JACOB: At the moment, 11 Bills are there. I will explain to you the details when I reply to the discussion.

डा० बलदेव प्रकाश (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जम्मू काश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर डेलिगेशन आफ पावर्स बिल प्रस्तुत किया गया है विचारार्थ, कंसिडरेशन के लिए । इस बिल को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जम्मू काश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, विधान सभा भंग हो चुकी है और कानून बनाने के अधिकार जो हैं वह संसद के अधिकारक्षेत्र में आ गए हैं । ऐसे अध्यादेश हैं जिनकी सीमा की अवधि समाप्त हो रही है और एक सप्ताह के अंदर अंदर वह अवधि समाप्त हो जाने के बाद वह रद्द हो जाएंगे और संसद के पास समय का अभाव है, वह विचार नहीं कर सकती । इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिए जा रहे है कि वह सभी अध्यादेशों, कानूनों जिनमें संशोधन होने हैं वह कानून बना सकें ।

महोदय यह विचारना होगा कि लोकतंत्र की व्यवस्था जो वहां पर समाप्त हुई है और आज जम्मू कश्मीर जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसके कारण क्या हैं ? कौन दोषी है उसके लिए । जम्मू-काश्मीर में आज सारी व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी है । सरकार की कोई रिट नहीं चलती । आतंकवादियों उग्रवादियों की रिट चलती है । करफ्यू लगा हुआ है गोलियां चल रही हैं निर्दोष लोगों की हत्यायें हो रही हैं अपहरण हो रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं और लगातार दो तीन साल से ऐसी रिपोर्टें आ रही है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या प्राकृतिक प्रकोप आ गया है या हमारी राजनीति के कारण आज काश्मीर इस संकट से गुजर रहा है ? मैं यही सदन के सामने रखना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या होती रही वोटों की राजनीति के लिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट किया, सत्ता में रहने के लिए सांप्रदायिकता का कार्ड वहां पर खेला गया और लोगों का भरोसा इस सीमा तक समाप्त हो गया कि आज वहां पर केन्द्र सरकार के प्रति विश्वास कम से कम घाटी के अंदर तो नहीं है । घाटी की जनता आज इस देश की केन्द्रीय सरकार से बहुत दूर जा चुकी है ।

श्रीमन्, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि 1982 में जब चुनाव थे उन दिनों में कांगेस की तरफ से सांप्रदायिकता का कार्ड खेला गया, खुल्लमखुल्ला जो यहां पर सांप्रदायिकता के बारे में दूसरों के ऊपर लांछन लगाते हैं आरोप लगाते हैं । क्या हुआ जम्मू काश्मीर में । उससे पहले ट्राइपारटाइट (त्रिपक्षीय) कांफ्रेंस पंजाब को लेकर यहां पर हुई थी । उस में एक तरफ सरकार थी, दूसरी तरफ अकाली पार्टी के लोग थे, अपोजिशन के सारे दल उसमें शामिल थे । उस त्रिपक्षीय वार्ता में सारी ही पंजाब की समस्या प्रायः हल हो चुकी थी । केवल यही बाकी था कि वहां पर जाकर ऐनाउसमेंट करना है । आखिरी समय में जाकर सरकार उससे फिर गई । उस समय इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं । केन्द्रीय सरकार जो फैसला हुआ था उससे पीछे फिर गई और उस फैसले को लागू नहीं किया गया क्योंकि 1983 में जम्मू-काश्मीर के अंदर

[डा० बलदेव प्रकाश]

चुनाव थे। अगर पंजाब को कुछ देना पड़ता तो 1983 में चुनावों में वोट मिलते या नहीं मिलते, यह सोचना एकमात्र लक्ष्य था। जब सोचने का एकमात्र लक्ष्य यह बन जाए, जब चुनावों की राजनीति के आधार पर ही देश को चलाने की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति हो तो उसके दुष्परिणाम होने निश्चित हैं। उसके दुष्परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। 1985 में नेशनल कांफ्रेंस के दो टुकड़े किये गये। एक हिस्सा उसमें से कांग्रेस के समर्थन से फारूख अब्दुल्ला से अलग हो गया और विरोध किया। क्यों किया? वहां पर फारूख अब्दुल्ला की सरकार नहीं रही और गुलशा की सरकार हो गई। उनकी सरकार बनी। मैं पूछना चाहता हूं सदन में कि वह कौन सा सिद्धांत था कि चुनी हुई सरकार को तोड़ करके दूसरी सरकार वहां पर कायम की जाए। किसने की वह? कौन सा राजनीतिक दल था जिसने यह सारा कुचक्र चलाया? केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने यह सब किया। यह कोई सिद्धांत है? गया राम आया राम वहां पर चला तो क्या वहां पर एंटी डिफेक्शन ला लागू नहीं होता? गुलशा की सरकार शेखअब्दुल्ला की सरकार बदतर साबित हुई। जब ऐसी सरकार वहाँ पर आई तो इनको यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। फिर केन्द्र की सरकार ने 1986 में इस सरकार को तोड़ा। वहां पर गवर्नर का, राष्ट्रपति का राज लागू किया। यह 1986 मार्च में लागू हुआ और 1986 नवम्बर में जो चुनाव हुए उसमें राजीव गांधी और फारूख अब्दुल्ला में साथ-साथ समझौता हुआ और उन्होंने चुनाव लड़ा। कौन थे फारूख अब्दुल्ला? यह वह फारुख अब्दुल्ला थे जो 1974 में पाकिस्तान गये थे और वहां पर मकबूल बट्ट उनके साथ थे। उन्होंने मिल कर बयानबाजी की थी कि काश्मीर का एक मात्र हल यह होना चाहिए कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। हिन्दुस्तान की जंजीरों से मुक्त होना चाहिए। फिर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। 1986 के बाद वहां पर फारूख अब्दुल्ला की सरकार आई। लेकिन वह सरकार भी नहीं चली। 1990 में फिर राष्ट्रपति राज लागू हो गया। मैं यह बताना चाहता हूं सदन को कि लगातार राजनीतिक खींचातानी के कारण से और सत्ता में रहने के कारण से सरकारें तोड़ी गई और सरकारें बनाई गई, सिद्धांतों की अवहेलना की गई। केवल सत्ता के आधार पर चलाई गई राजनीति का यह दुष्परिणाम है कि आज उस प्रदेश के अंदर कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है।

आज जो काश्मीर की वर्तमान व्यवस्था है उसके बारे में बताना चाहता हूं। चुनाव क्यों नहीं हो सकते वहां पर? नहीं हो सकते मैं भी इससे सहमत हूं कि अभी नहीं हो सकते। लेकिन कब हो सकेंगे? आज उस प्रदेश से आये हजारों, लाखों व्यक्ति दिल्ली आये हुए हैं, जम्मू के अंदर कैम्प में बैठे हुए हैं। एक-एक कमरे के अंदर 15-15, 20-20 आदमी एक ही परिवार के बैठे हुए हैं। सरकार पर आश्रित हैं। सरकार की थोड़ी बहुत दी हुई तनख्वाह से अपना पेट भर रहे हैं। जबतक वे लोग जम्म-काश्मीर जाकर वोट डालने की स्थिति में नहीं आ जाते तबतक वहां पर चुनाव होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह स्थिति कैसे आ सकती है? निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है क्या? वहा पर क्या आतंकवाद समाप्त हो जायेगा? क्या दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू में कैम्पों में बैठे हुए लोग वहां जाकर वोट डाल सकेंगे? अगर नहीं डाल सकेंगे तो चुनाव भी नहीं हो सकेंगे। क्या पंजाब की तरह चुनाव होंगे? क्या असम की तरह चुनाव होंगे कि एक-एक प्रत्याशी सौ-दो सौ वोट लेकर विधान सभा का सदस्य बना हुआ है? पंजाब में ऐसा हुआ है कि 298 वोट हासिल करके एक प्रत्याशी विधान सभा का सदस्य चुना गया। एक ही वर्ग के लोग बसों में, ट्रकों में भर कर एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ पर ले जाया गया। पंजाब में 8-10 परसेंट वोट पड़े और वहां पर सरकार बन गई। क्या ऐसा ही कोई खेल केन्द्र की सरकार जम्मू-काश्मीर में खेलने जा रही है?

इससे जनता का भरोसा सरकार के अंदर बन सकेगा ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोकतंत्र की जड़े खोद रहे हैं। लोकतंत्र लोक सभा या संसद की बिल्डिंग का नाम नहीं है। विधान सभा के भवन का नाम नहीं है। लोकतंत्र एक सिद्धांत, एक परम्परा, एक स्वस्थ व्यवस्था प्रणाली का नाम है। जिस प्रणाली में सिद्धांतों को उचित स्थान मिले, सिद्धांतों के लिए व्यक्ति सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो। यह नहीं होना चाहिए कि सत्ता के लिए व्यक्ति सिद्धांतों को छोड़ करके इधर उधर से दल बदलवा करके, मेम्बरों को तोड़ करके, रिश्वत दे करके, लालच दे करके और हिंसा के द्वारा, डर के द्वारा अपनी सरकार कायम रख सके। इसका नाम लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब जमूरियत नहीं है। लेकिन आज वह सब कुछ हो रहा है। इस तरह से तो जमूरित की जड़ें कमजोर होंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESHDESAI): Only four minutes are left. You may speak on the provisions of the Bill now.

डा० बलदेव प्रकाश: मैं प्रोविजन्स पर ही आ रहा हूं। जो एक्ट के अन्दर प्रोविजन्स हैं उसमें क्या है? वहां पर विधान सभा नहीं है और कानून बनाने के अधिकार प्रोक्लेमेशन के बाद विधान सभा से हट कर संसद के पास आ गया। अब संसद के पास समय नहीं है। अगर संसद के पास समय नहीं है तो इतनी देर तक हम क्या करते रहे? वहां पर जून के महीने की तनख्वाह लोगों को नहीं मिली है। जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं। आठ हजार लोगों को जून के महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। कैम्पों के अन्दर जो विस्थापित बैठे हुए हैं उनको खाने-पीने के लिए महीने में जो मिलता था वह भी नहीं मिला। वहां पर ट्रेजरी खाली है। इस वित्त वर्ष के दो महीने बाद जम्मू-काश्मीर की सभी ट्रेजरीज और खजाने खाली हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून बना नहीं सकते। जब कानून बनाने का अधिकार संसद को था तो एक व्यक्ति को वह अधिकार देना, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, कहां तक उचित है। राष्ट्रपति को, एक व्यक्ति को, एक प्रदेश का कानून बनाने का आप अधिकार दे रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है? "...the President shall, whenever he considers it practicable to do so, consult a Committee constituted for the purpose, consisting of..."

जब कभी भी उनको अच्छा लगेगा, प्रेक्टिकल और व्यावहारिक लगेगा, तब तो विचार करने के लिए उस कमेटी से विचार कर लेंगे और अगर उनकी मंशा नहीं होगी, उनके विचार में इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो प्रेजीडेन्ट कानून बना लेंगे। यह कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अगर वहां पर विधान सभा नहीं है और संसद यह काम कर नहीं सकती तो क्या उसके लिए आलटरनेटिव या विकल्प यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह बिलकुल ठीक नहीं है। यहां स्पष्ट शब्दों में व्यवस्था होनी चाहिए और इसको डिलिट होना चाहिए। "whenever he considers it practicable."

राष्ट्रपति अगर कानून बनायें तो तभी बना सके जब उस कमेटी के साथ जो इस परपज के लिए कांस्टिट्यूट की गई उसके साथ विचार करने के बाद वे कानून बना सके और तभी उसके अन्दर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का पुट शामिल कर सकेंगे। उसके बगैर यह नहीं हो सकता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम बहुत देर तक वहां चुनावों को रोक नहीं सकते हैं। मैं अंत में वाईंड अप करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि हम कितनी देर तक इस तरह से हिन्दुस्तान में राज चला सकते हैं। अभी वहां पर इलेक्शन नहीं हो सकता। ला एण्ड आर्डर ठीक नहीं है। शांति और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, आग लगी हुई है। इस प्रकार से कैसे राज चलेगा। आप क्यों कुछ नहीं करते हैं। ऐसी दिशाहीन नीति को बदल कर एक दृढ़ और ठीक दिशा

[डा० बलदेव प्रकाश]

वाली नीति जम्मू-काश्मीर पर लागू क्यों नहीं करते हैं और वह नीति यह है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है, अब तक जो हो रहा है उसमें आप आज एक फैसला करते हैं और दूसरे दिन दूसरा फैसला करते हैं। कभी एक गवर्नर को भेजा जाता तो दूसरे दिन दूसरा गवर्नर बदल दिया जाता है। राजनैतिक कारणों से गवर्नर बदल दिया जाता है। क्या कारण है कि आपने राजनैतिक कारणों से गवर्नर को बदल दिया? वहां की जनता चाहती थी कि वह गवर्नर वहां रहे, लेकिन आपने उस गवर्नर को हटाकर दूसरे को वहां भेज दिया। इस प्रकार से राजनैतिक कारणों से अगर काम किया जाएगा तो कोई भी हल संभव नहीं है। वहां धारा 370 क्यों लागू है? जब जम्मू-काश्मीर का विलय हो चुका है तो बाकी प्रदेशों की भांति सभी बातें वहां लागू क्यों नहीं होती हैं? जम्मू-काश्मीर का एक व्यक्ति हिन्दुस्तान में जहां करोड़ों रुपए की सम्पत्ति खरीद सकता है वहां कोई भी हिन्दुस्तान का व्यक्ति वहां सिर छिपाने के लिए एक झोंपड़ी भी नहीं बना सकता और जब तक इस प्रकार की दीवारें खड़ी रहेंगी तब तक कोई हल नहीं निकल सकता है।

आप ये दीवारें तोड़ेंगे। सारा हिन्दुस्तान एक है। चाहे कोई भी प्रदेश हो, वह हिन्दुस्तान का वैसा ही हिस्सा है हिन्दुस्तान एक है। चाहे कोई भी प्रदेश हो, वह हिन्दुस्तान का वैसा ही हिस्सा है जैसे कि जम्मू और कश्मीर है। जब तक हम ये दीवारें खड़ी रखेंगे, तब तक कोई हल नहीं हो सकेगा यह मैं सदन के सामने बड़े अधिकारपूर्ण शब्दों में कहना चाहता हूं। आप सौ कहिये कि यह ऐतिहासिक अवस्था है, अब हम बदल नहीं सकते। लेकिन सिद्धान्तों के सामने ऐतिहासिक अवस्थायें टिक नहीं सकतीं। यह एक सिद्धांत है कि सभी प्रदेशों के एक जैसे अधिकार होने चाहियें चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो।

एक और बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। यह भी बात आ रही है कि 1953 से पूर्व की स्थिति वहां पर लागू कर दी जाय। 1953 में जो स्थिति थी, हम लोग जो अन्य प्रदेशों से वैष्णोदेवी के दर्शन के लिये जाते थे, हमें परमिट लेना पड़ता था। परमिट लेकर हम जम्मू और कश्मीर जाते थे। वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में जम्मू और काश्मीर नहीं था। तो क्या आज हम फिर चाहते हैं कि अगर आज फिर हमें वहां जाना हो तो हम परमिट लेकर वहां जायें। क्या वह विदेश है, क्या कोई दूसरा देश है? क्या आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र से निकालना चाहते हैं? मैं सरकार को आज यह वार्निंग भी देना चाहता हूं– हम धारा 370 को भी हटाने की मांग कर रहे हैं–अगर कोई ऐसा निर्णय जिसमें 1953 से पूर्व की स्थिति पर लाने की बात कही जायेगी, या ऐसा करने की कोशिश होगी, तो उससे हम कश्मीर की समस्या को और उलझायेंगे और उसको ऐसी अवस्था पर ले जाकर खड़ी कर देंगे जहां से वापस लौटने का शायद कोई रास्ता न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Jammu and Kashmir State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1992.

Before I say anything on this Bill, I would like to say just one word in regard to the speech which has been made by the preceding hon. Member. The observations which the hon. Member has made are not conducive to improving the situation in Kashmir, which is too grave to be dealt with on such partisan lines. The situation is so grave that it calls for unity of action on the part of the entire nation and all political forces in the country.

So far as this Bill is concerned, as the hon. Minister has said, article 356 provides that whenever a Proclamation is issued, it may be provided in that Proclamation that the powers of the State Legislature may be exer-

cised by Parliament. Rightly so, because, when a State Legislature is dissolved, there has to be some authority which should be in a position to make laws for that State which comes under President's rule. That is why article 356 provides that the Proclamation may make a provision empowering Parliament to make laws for the State coming under President's rule. But then, the Constitution-makers thought it fit to make an exception provision, namely, article 357. Article 357 provides that whenever there is such a Proclamation and when such a Proclamation contains a provision that Parliament may make laws for that particular State, Parliament may also make a law making it competent for the President to make laws for that state. In other words, Parliament may delegate its authority to make laws to the President himself.

Now, the question is, why was this provision, article 357, introduced into the Constitution by the founding fathers of the Constitution? Article 357 is not being introduced by the Bill. It has not been introduced by this Government. Article 357 was introduced by the founding fathers of the Constitution. The reason was that an urgent exigency of situation may arise in a particular State which comes under the proclamation under article 356, which may call for an emergent action for enactment of a particular law to deal with a particular situation and it may not be possible o follow he normal procedure of enacting that law through the Parliament. In order to deal with an urgent exigency of situation, there may be a provision which may be necessary authorising the President to make a law for that particular State to deal with that particular situation.

An argument has been raised that this amounts to usurpation of powers of the Parliament. I submit, Sir, this argument is an argument in futility. If this argument is to be taken as valid, article 357 has to be effaced from the pages of the Constitution. Article 357 in terms says that Parliament may make a law empowering the President to make the laws for that particular State. Where is the question of usurpation of the powers of Parliament by the President? The question of usurpation of the powers of Parliament by the President, therefore, does not arise.

Sir, what is the situation which is prevailing in Kashmir today? I have said that the situation in Kashmir is extremely grave. Pakistan has launched a calculated and deliberate policy of bleeding India into disintegration. All the activities of Pakistan are not merely encouragement of terrorism in Kashmir or import of terrorism into Kashmir. They amount to a blatant, naked aggression against India under international law. Pakistan is training the armed bands on her own soil. Pakistan is arming those armed bands. Pakistan is hurling those armed bands across the frontiers of India into Kashmir to use not only weapons against the civilians, but to fight the security forces and the armed forces of India; and Pakistan is hurling those armed bands across the frontiers of India many a time under the cover of heavy artillery bombardment. All these activities under the international law amount to aggression. The expression 'aggression' has been used in the Charter of the United Nations. It has been particularly used in the Chapter dealing with the powers of Security Council. When the Charter of the Security Council was framed, first it was adumbrated that 'aggression' should be definied in the Charter itself, but the expression was left undefined on the ground that this may lead to rigidity. Therefore, the expression 'aggression' was not defined in the Charter of the United Nations. But in 1967, the General Assembly constituted a Committee for the purpose of defining the expression 'aggression' as occurring in the Charter of the United Nations. This

[Shri Madan Bhatia]

Committee gave a definition of 'agression' and the definition included certain armed bands of mercenaries crossing the frontiers into another State to fight its armed forces to use weapons against that country.

[**The Vice-Chairman (Shri M. A. Baby)** in the Chair]

This definition of the aggression given by that Committee was adopted unanimously by a Resolution passed by the General Assembly of the United Nations. I submit, Sir, all the activities of Pakistan constitute aggression as defined by the United Nations by means of the Resolution passed in 1969. It is this situation which we are facing in Kashmir and it is for this purpose that it is highly necessary, apart from the reasons which have been given by the hon. Minister, that the President should be armed by this Parliament with the powers to pass such laws as the urgent exigency of a particular situation calls for.

I submit, Sir, that so far as article 357 is concerned, there are no restrictions when this law is made, which may be placed upon the President when this power is exercised. Parliament can pass a blank law saying that the President shall have the power to make Acts for this particular State. No restrictions need be placed upon the power of the President while making these laws. Secondly, article 357 goes a step further. It says, the President may further delegate his power which is conferred upon him by Parliament.

But what is this Bill? This Bill does not go that far. This Bill, on the contrary, contains two very salutary restrictions which need not be there of article 357. The first restriction, which is important, provides that whenever the President seeks to enact any law for the State of Jammu and Kashmir, the President shall consult a Committee constituted for the purpose, consisting of 10 Members of the House of the People and five Members of the Council of States. Does it not contain a control by Parliament on the powers of the President? I submit, Sir, it very much does. The second control which is exercised by Parliament, under this Bill, is provided by clause 3, which says that every such Act shall be placed before both Houses of Parliament and each House shall be entitled to make such modifications as it thinks fit to this particular Act, and if that modification shall be incorporated by the President in the law itself. These are the two salutary restrictions adumbrating the control of Parliament over the Act which may be made by the President under this law in relation to the State of Jammu and Kashmir. These restrictions might not have been there, were not required to be there, by virtue of article 357, but the Government, in its wisdom, recognizing the importance of the whole situation and recognizing the fact that every step which is to be taken in Kashmir must bear the stamp of consensus of the entire nation and of all the political parties and of all the political forces, has considered it wise to introduce these two provisions in this Bill itself.

Therefore, Sir, I strongly support this Bill and I commend these measures and I commend the spirit in which this Bill has been brought forth before this honourable House by the Government, and I plead with the entire House to support this Bill unanimously. Thank you, Sir.

मुफ्ती मोहम्मद सईद (उत्तर प्रदेश): वाईस चेयरमैन, सर, यह जो बिल लाया गया है राज्य सभा के सामने इसकी बहुत जरूरत है और जो कानून, जो लाज गवर्नर रूल की मुद्दत में पास हुये हैं, उनकी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है या हुई है।

तो इसलिये इस बेसिक सवाल का यह तो होना ही है जरूर, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां भाटिया साहब ने कह दिया कि प्रेजीडेंट को पावर है, प्रेजीडेंट को पावर्स है, लेकिन यहां जो आपने यह कह दिया है कि पार्लियामेंट के पास समय नहीं है, टाईम नहीं कि जम्मू-कश्मीर के जो ला नाफिस करने हैं, उनको पास करने के लिये टाईम नहीं है। मैं समझता हूं कि जब आप कहते हैं कि Kashmir is a national issue. कश्मीर में जो आजकल के संगीन और सीरियस हालात हैं, पार्लियामेंट के बगैर और कौन-सा इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसकी क्रैडिबिल्टी सारे मुल्क में है, सारे इलाके में है – यहां इसको डिसकस नहीं किया जा रहा है। जब आप कहते हैं कि टाईम ही नहीं है, तो आप इस इशु को अडल्ट्यट करते हैं, इसका वजन कम होता है। तो यह एक बात है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रेजीडेंट है, अभी तक जिन स्टेट्स में गवर्नर रूल हुआ है, उन स्टेट्स में पार्लियामेंट को छोड़कर सिर्फ प्रेजीडेंट को पावर दिया गया है, ऐसा मेरे जहन में कोई प्रेजीडेंट पोस्ट-इंडिपेंडेंस पीरियड में कई नहीं है जहां प्रेजीडेंट को पावर बनाने के लिये दिया गया है। इन्होंने कह दिया... (**व्यवधान**)

SHRI MADAN BHATIA: Sir, I would like to correct the hon. Member. Similarly a law was passed in 1971 in regard to the State of West Bengal.

मुफ्ती मोहम्मद सईद: मैं यह कह रहा हूं कि कोई स्टेट–पंजाब की स्टेट है जहां कश्मीर से ज्यादा मुद्दत तक गवर्नर रूल रहा। उस विषय में उस स्टेट के बारे में ऐसा नहीं किया गया है। You are giving a wrong signal. You are giving a wrong message to the people of the country and to the people of Kashmir.

एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप शुरू करना चाहते हैं। तीसरी बात यह जो कह दिया कि इमरजेंसी होगी, तो प्रेजीडेंट को कानून पास करना होगा। क्या करेगा वह ? पार्लियामेंट के सामने आयेगा। जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट को आर्डिनेंस पास करने का, इशु करने का अख्तियार है। वह इन लाज के बारे में, जो लाज रह चुके होंगे, हम इस बात की पूरी ताकत से विरोध करेंगे कि पार्लियामेंट से यह अख्तियार लिया गया है। पार्लियामेंट में वहां के क्या कानून पास हुये, क्या कानून पास करते हैं— जम्मू-कश्मीर के क्या हालात है। हमारी तरफ से इतनी बड़ी सारे देश की सावरेंटी यहां हैं, सारे देश के नुमाइंदे यहां हैं, सारा थिंकटैंक यहां हैं, आपको सुझाव दिये जा रहे हैं। अगर आप यह नहीं करना चाहते, अगर आप कहते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास टाईम नहीं है, यहां पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है दोनों हाऊसेज की, जो स्टैंडिंग कमेटी इन लाज को एक्जामिन करके पार्लियामेंट को पेश करे ताकि पार्लियामेंट में ज्यादा वक्त नहीं लगे।

चौथी बात, जब आपने एक कन्सल्टेटिव पार्लियामेंट की कह दी है कि पन्द्रह मेम्बरों की कन्सल्टेटिव कमेटी होगी, उसमें भी it is not mandatory on the President to consult the Members of Parliament or to consult the Sub-Committee. It is the discretion of the President.

तो मेरे ख्याल में इस कानून को हम अपोज करेंगे और ऐसा कानून आप पास करेंगे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप वहां करना चाहते हैं, उसका खंडन करना चाहते हैं, इस बात की क्रडिबिल्टी नहीं है।

पांचवीं बात, जो हम यहां कहते रहे कि इसी दायरे में हम बात करना चाहते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने यह कह दिया कि कश्मीर में चुनाव होने चाहियें। इसमें भी अच्छी

[मुफ्ती मोहम्मद सईद]

बात है । अल्टीमेट तो लोगों को ही ही साथ चलाने का सवाल है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी ग्राउंड रियैलिटी वहां ऐसी नहीं है । यह बात ठीक है कि लोगों के जहन में– The mood of the people has changed. उस वक्त की बात नहीं कि आजादी आज आ जायेगी, कल आ जायेगी ।

आज कश्मीर के लोगों को – मैं सही कहता हूं––जो बात मैं आपसे कहता हूं वह सही कहता हूं, उनके सोचने में फर्क आ गया है । To that extent there is an improvement in the situation. क्यों पाकिस्तान ने हजारों कश्मीर के नौजवानों को– Kashmir is bullied इस्तेमाल किया गया है, एक्सप्लायट किया है । हम यह कहना चाहते हैं कि जो मुल्क ने कश्मीर को दिया है, युनिवर्सिटी तक वहां– education is free up to the university level. टैक्नीकल एजुकेशन भी फ्री

4.00 P.M. है वहां तो सब से पहला जो हमला हुआ वह वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर हुआ । स्कूल जलाये गये, कालेज जलाये गये पुल जलाये गये । तो एक सारा सिस्टम जो कश्मीर तरक्की की राह पर था जहां डिवैलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था यह अहसास हुआ है कि इन जवानों को यह नहीं कि दो हजार, चव्हाण साहब ने कहा दो हजार ए०के०–47 का सीजर हुआ है, लेकिन नहीं आज तक जो सीजर हुआ है ए०के०-47 का वह दस हजार का है । देखना चाहिये कितना सामान आ रहा है । दूसरा कश्मीर में नहीं कहता हूं स्विटजरलैंड कहता हूं लेकिन 84–86 में कश्मीर एक ऐसा डेस्टीनेशन है कि इट वाज फार आल सीजंज । ऐसे इंतजाम किये गये थे कि गुलमर्ग, पहलगांव में बराबर स्विटजरलैंड की तरह स्कीइंग का प्रोग्राम विंटर के लिये डिवैलप किया गया । वहां तिल धरने के लिये जगह नहीं थी जून, जुलाई में ही नहीं बल्कि विंटर में भी टूरिस्ट आते थे । दूसरा कम्प्यूटर इंटस्ट्री इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्री के लिये भी वहां मौसम साजगार है, उसमें भी तरक्की हो रही थी । लेकिन लोगों को यह एहसास है कि पाकिस्तान वहां के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है । मैं कहता हूं कि 1947 के बाद पहली दफा यह एहसास हुआ है हमारे जवानों को तबाह कर दिया गया । इसी तरह से मिलिटैंटस की तरफ से भी एक्सैसस एक्सटोशंस हुये हैं । एक ऐसा माहौल हुआ है । उस वजह से कोई वहां पोलिटिकल प्रोसैस नहीं हुआ । मौलवी इफ्तखार साहब के यहां मिर्जा इस्माइल आये थे एक जमाने में बारामूला से कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेजीडेंट थे । उनको मिलने आये बाहर उसको गाड़ी में लिया और वहीं कत्ल कर दिया गया । मेरा यह कहने का सवाल है यह सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इनका मसला नहीं यह पूरे देश का मसला है, पूरे नेशन का मसला है । इसको कैसे किया जाय । जब आप चुनाव की बात करते हैं उम्मीद पैदा होती है, लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, काश्मीर इज नाट ओनली ए काश्मीर वैली, काश्मीर में जम्मू भी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने माइग्रेंटस काश्मीर में शायद जितनी एक्सैसैस मिलिटैंटस ने वहां की जम्मू में एक कम्यूनल हारमोनी का माहौल था, काश्मीर का हिन्दू ही नहीं भागा है, काश्मीर का मुसलमान भी भाग रहा है, बंगलौर में, दिल्ली में जामिया मिलिया में, अलीगढ़ में, जम्मू में लाखों की तादाद में काश्मीर का मुसलमान भाग कर आया है । जिसको नहीं लगता है जिसको कि बच्चे को तालीम देनी है, शिक्षा देनी है, वह नही समझता है । हजारों की तादाद में लोग आते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं । उनको लोग

अगवा करके पाकिस्तान ले जाते हैं। मेरा यह कहने का है कि सब को, मैं पिछले दिनों श्रीनगर में था। पाकिस्तान की आई०एस०आई० की टीम हर महीने वहां पर यह देखने के लिये आती है कि यह कमजोर क्यों हो रही है मुल्क । वह एक तरह से हरेक अपना वहां जाल बिछाये हैं। वह डे टू डे क्या होता जैसे किसी ने कह दिया था कि टेलीफोन करना हो क्या करें आप । किसी को टेलीफोन करना होता है तो हर जगह टेलीफोन कर सकता है । शाम को श्रीनगर से टेलीफोन किया हर जगह हुआ । तो मेरा यह कहना है कि एक तो यह बिल मैं कहां चाहूंगा दूसरा में कहना चाहूंगा कि जब ये पोलिटीकल प्रोसैस की बात करते हैं, जब ये इलैक्शन की बात करते हैं, मेरा यह कहना है कि ग्राउंड रिएल्टी जो जम्मू-कश्मीर की है, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है उसमें सिचुएशन में नार्मलाइज जैसे यहां डा० बलदेव प्रकाश जी ने कह दिया एक न्यूज पेपर ने दिया है, काश्मीर जम्मू-काश्मीर में जो एंप्लाइज की पे है पिछले दो महीने से वह उनको नहीं मिली है। जो काश्मीर से माइग्रेट जम्मू में हैं उनकी रिलीफ के लिये भी पैसा न है, कंस्ट्रक्शन काम के लिये पैसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एक सौ करोड़ दिया कोई एमरजेंसी एड के लिये जम्मू काश्मीर बैंक से उन्होंने 600 करोड़ उधार लिया है। वह यह पैसा रिलीज करने को नहीं है। अगर यह इमरजेंसी है अगर यह नेशनल इश्यू है ,अगर यह देख रहे हैं कि it has become a bed-rock of international intrigues. जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो इसमें कहने की क्या जरूरत है, जितना सामान जितना पैसा वहां आ रहा है तो आपकी यह प्रायरिटी नहीं, वहां दिवालिया है । वहां लोगों के लिये तनख्वाह नहीं है, डवलपमेंट के लिये पैसा नहीं है सारे सेंट्रल प्रोजेक्टस बन्द पड़े हैं । तो इसकी तरफ भी मैं होम मिनिस्ट्री का ध्यान चाहूंगा और खाली होम मिनिस्ट्री से ही नहीं कहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि इसका टोटल व्यू लेना चाहिये । इसके लिये मेरा सजेशन है कि बहुत अच्छा होगा अगर हमारा यह सजेशन मान लिया जाय कि पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी रहे, खाली इसी एक इश्यू को लेकर नहीं बल्कि कौनसा कानून पास करना है, क्या स्ट्रेटजी, आप फार्म करना चाहते हैं, इस सबको सुलझाने के लिये। तो यही एक रास्ता है और अगर आप प्रेजीडेंट को अधिकार देंगे तो मुझे लगता है कि वह अच्छा नहीं रहेगा । It will be a wrong precedent again. You will be making an exception in the case of Jammu and Kashmir. पंजाब में 5 साल गवर्नर रूल रहा, लेकिन वहां ऐसा कानून पास नहीं हुआ। इसलिये मेरी गुजारिश है कि हमारा जो सजेशन है, उसे मान लिया जाये।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, when I rise to support this Bill, I have feelings of anguish. The Valley of unmatched beauty, the Valley of peace, the Valley of joy which we all visited so often in a year has today become unfortunately a graveyard. Violence has become the order of the day and curfew is imposed for days after days. Everything has come to a standstill. Today we are asked to support the Bill which is a Constitutional necessity. I think, it is the duty of every Member of Parliament to ensure that all Constitutional hurdles are overcome and that the Constitutional process goes on. This is a very exceptional psovision to which I will come a little later. We would not Bill today but for the fact that on a given day just by the whim of an individual, the elected Legislative Assembly of Jammu and Kashmir came to be dissolved. I am really pained

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

because at least two of the leading figures, the then Home Minister and the then Governor, who played such a great role and a key role in bringing about this disastrous change are present in the House today. I cannot understand with what face they can defend their total unconstitutional action, firstly, by sending a Governor who was not acceptable to the then Chief Minister of that State. Secondly, they dissolved the State Assembly without the concurrenc of anyone and contrary to section 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir. Please remember, if today India is proud of anything, it is because it is the largest democracy in the world. We have preserved it under most adverse circumstances. We have preserved it under great strain and they crushed it in Jammu and Kashmir as if they have crushed a fly. Today all people are speaking against this Bill. I think that position would not have been there if there had been that buffer of the elected representatives between the Government and the people. I am not saying this for the sake of saying. It is very easy to lay the blame on the other side. But I said it then and I am saying it now that this is far too fundamental. It has nothing to do with the likes of 'X' or the dislikes of 'Y'. But it has something to do with the very basic structure of our Constitution, the Constitution which ensures democracy, the Constitution which ensures an egalitarian and secular society. I may tell you the whole picture, the whole history, the whole saga of Kashmir, as it unfolded. I go back to that day when Maharaja Hari Singh signed an instrument of accession on 27th October, 1947 and provided for that pernicious clause 7: There were 562 Princely States then. We brought 561 under our umbrella. One State remained out and that was the State of Jammu and Kashmir because the Maharaja of Kashmir could not make up his mind. And even when he made up his mind ultimately, he provided clause 7 in the instrument of accession stating, "Nothing in this document shall be deemed to commit me....."—that is, Maharaja Hari Singh—" .....in any way to acceptance of any future Constitution of India and to fetter my discretion." Even the Constitution of India which was on the anvil at that time was not going to be accepted. It is most fascinating history how step by step we not only fought in the battle field but in the Constitutional field too to integrate Kashmir into the Constitution of India. It is important because Article 356 and 357 were made applicable to Jammu and Kashmir early in January 1965 followed by a war in March that year. The war ultimately ended in the Tashkant Pact. It is something very, very interesting. But there is no time for us. I think the total time given for this very, very important subject is hardly for this one hour or one hour and fifteen minutes.

SOME HON. MEMBERS: Two hours.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: But I do want to place this responsibility before the House. Today, when we talk of democracy, we should remember that. As a Member of Parliament, I am worried. I know that this is an infraction of law, of Parliament's power, and I am slightly worried. But that is only at the first blush. A deeper consideration of the provisions will show that the objections which have been made are totally unsustainable.

The objections, as far as I have heard, are three. The first objection, as far as I conceive, is that they feel as if this is an abrogation of Article 370. No, this is not an abrogation of Article 370. Article 370 should be debated. I think the time has come when we should debate Article 370 for a full day and come to a concrete decision on that because it was a temporary measure. But several temporary measures have continued till today. When Articles 356 and 357 were made applicable to Jammu and Kashmir, a propaganda was made that that was to see that there was no democracy in Jammu and Kashmir. The same propaganda is being made now

as if by this enactment we will be abrogating Article 370. Article 370 will continue.

Then they say that the provision of a Consultative Committee of fifteen members is not mandatory. I think the words are very clear. If I am permitted to read them, they are as follows:

> "Provided that before enacting any such Act the President shall, whenever he considers it practicable to do so..."

Therefore, unless it is impracticable —and that can be only on the ground of urgency or emergency—he has to consult. The words are "shall consult a Committee constituted for the purpose". Now, if ever the President were to do it on his own, when it was practicable for him to consult, such an Act would be void *ab initio*. It would be *non est*. Please do not forget that our power is not taken away. Our representatives on the Consultative Committee will be there all the time.

The second point that is raised is : What happens when such an Act is passed? Kindly see clause 3(3). It reads:

> "Every Act enacted by the President under sub-section (2) shall, as soon as may be after enactment, be laid before each House of Parliament."

Therefore, there is an obligation to lay it before us. And clause 4 reads as follows:

> "Either House of Parliament may, by resolution passed within thirty days from the date on which the Act has been laid before it under sub-section (3), which period may comprised in one session or in two successive sessions, direct any modification to be made in the Act and if the modifications are agreed to by the other House of Parliament during the session in which...."

the Bill has been so laid before it, such modifications shall be given effect to.' Therefore, it is a complete provision for what is called a ratification. It has to be ratified by this House and any modifications which are made by the Parliament are binding. I think this completely preserves the sovereignty of Parliament in the matter. Ultimately, let me come to the brass tacks and I have done. What are the conditions under which we are asking to delegate these powers to the President? The conditions are the same which were there in 1965, the condition are the same which were there in 1947 when the raiders raided India. Please remember, today the war by proxy is on. The same kind of infiltration, the same kind of training, the same kind of supplying arms, the same kind of funding on a much larger scale, the same kind of sending the raiders across the border is going on because Pakistan has nothing to look at. The Afghan issue is over. Let us not disillusion ourselves. Therefore, we pass this bill under the most emergent situation that could have ever faced Kashmir. It is our duty to do it. What Acts are on the anvil which will get lapsed if we do not give this power? There is the Jammu and Kashmir (Disturbed Areas) Act, the Jammu and Kashmir (Public Safety) Act, the Jammu and Kashmir (Representation of People) Act which deals with the question of delimitation, and a very laudable thing which was done by hon. Mr. Jagmohan, that is the formation of Mata Vaishno Devi Trust, even that Act will lapse unless this is done.

Now, the point which I am making is that we are doing it out of compulsion; we are doing it out of necessity; we are doing it out of our duty as Parliament to save the Consituation and therefore, to that extent, we must support it.

Three things flow from the current situation in Kashmir the proxy

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

war as one nation with one voice, just as we reacted to the doings of the then Home Minister and the then Governor. I do not know why one of the Leaders of Opposition took the *Ekta Yatra* only up to Jammu and Kashmir. He should have taken it up to the Pak occupied territory. That would have been a logical thing. The point which I am trying to make is that there should not be any failure on our part.... (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: If you had provided a helicopter, he would have gone.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: If it had not been shot down! First of all, we must fight this unsurgency and the second point is the article of faith with all of us, that is our pledge to the nation to restore democracy. We have been successful in having elections in Punjab. I am quite confident that it won't be long before we have election in Jammu and Kashmir by which time this measure will automatically lapse. With this, I support the Bill.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I rise to strongly oppose this Bill. The Bill is asking the Parliament to forego its right to make enactments for the State of Jammu and Kashmir and for what reasons? The reason is, Parliament has no time to do it. I feel this is atrocious and that is why I cannot accept this Bill. I strongly oppose it. Sir, why has the Government come out with this Bill? I will be glad if the Home Minister listens to me because he has to reply to it. Can you please draw the attention of the Home Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mr. Home Minister, your attention is being drawn.

SHRI SUKOMAL SEN: The Home Minister is supposed to reply to this debate. (Interruptions) We know what he wil say and what he will do. Sir, what for has the Government come out with this Bill? For the last few months or few years what has the Government done? What is the situation in Jammu and Kashmir today? Because the Governor's rule is still to exist, still to continue and since Parliament is preoccupied with other business, they are not in a position to make enactments, so leave it to the President! This is most undemocratic, unacceptable. Sir, the point is the Government is solely responsible for the situation that is obtaining in Kashmir now. They have not yet been able to control the situation. They are yet to decide any political initiative in respect of settling the Kashmir issue.

In the last Budget session they talked of holding elections. Without creating a proper atmosphere for holding elections where the people can exercise their franchise, their right to vote, they are talking of elections! So, no democrat can oppose elections. Any democrat will support elections, whether it is Kashmir or any other State, but the democrat must also see that the people take part in the elections. If we conduct fracical elections, what would be the result? Of late, the Government has conducted elections in Punjab. What are the results, what type of elections are these, what percentage of people have voted in the elections?--all these questions come up. If the Government thinks that in the name of democracy they want to strengthen their position in the Lok Sabha since they are in minority, get some Members from Jammu and Kashmir and get some Members from Punjab. If that is the design, I would strongly oppose it. I would advice the Government, create a situation where the people can really exercise their votes, where the pople can take part. Despite the threats from terrorists, it is only in these conditions that elections could be held and only a Government that will be formed of

Members who are elected, can claim legitimacy. Otherwise, holding of farcical elections only to add some strength to their numbers in Lok Sabha will add insult to injury. Sir, the question is: What is the political initiative? The political initiative has not yet been as we have demanded. On the contrary, to prepare for the elections the work of delimination has already been started. One day they will declare the lists. I feel that the question of Kashmir is so serious that it cannot be tackled in this light-hearted fashion. True, Pakistan is creating problem there, it is creating trouble there. All those persons who are trained in Pakistan, are sent back to Kashmir and they create problems. And I also know that after all the political changes and turmoil in Afghanistan the problem in Kashmir may be further intensified. Some of them who are in Afghanistan may be diverted to Kashmir also to add to the strength of terrorists there. These are all facts. So what is the solution Sir, I would like to ask the Government to see what role the people of Kashmir had played in 1947. They fought boldly and courageously against the Pakistani invaders. They fought for integration with India. They are the people of Kashmir. And there was no communal strife there. Though Hindus were in absolute minority, Hindus and Muslims lived together amicably and there was no communal problem. But now the situation has completely changed. Who is responsible? The manner in which they have tackled the Kashmir situation, the manner in which they have tried to foist their own party in Jammu and Kashmir, has become the bone of contention, that has become the main reason for this situation in Kashmir. The National Conference has a long tradition of fight and struggle. It was dearest to the heart of hearts of the Kashmiri people. By hook or by crook they tried to dislodge it. They got a government formed with their puppets. They shared power with the puppets. They regged the elections; electio are made farcical and they did precious little for the development of the culture and economy of Kashmir. There are so many educated Kashmiri youths. They are for jobs. How many Kashmiri Muslims are appointed in Government service or any other service? Bit by bit they felt alienated, alienated from the Union of India, alienated from the Governemnt of India and Pakistan took advantage of this. Pakistan propagated, a vicious propaganda was made, "look, you fought for the integration of India; now, look at the situation where you are being treated not as a part of India, but as if you are outside India. So, why don't you join Pakistan?" People are misled. The youths are misled. Unemployed youths who do not find any future for them are misled by Pakistani ISI, intelligence bureau and Pakistan Government. They were traied and they were sent back for terrorism so that Kashmir can secede from India and remain independent or join Pakistan. Some outfits want complete integration of Kashmir with Pakistan and some outfits want independent Kashmir. Not that they are all united. When the terrorists started killing, extorting money, torturing the local people and torturing the Muslim community itself, many of the people in Jammu & Kashmir got disgusted with terrorists also. We have to see the situation in that context. There was some possibility for improving the situation as because of the behaviour of the terrorists people got disgusted. At the same time, we find that some party from our country has further worsened the situation. I would refer to the Ekta Yatra of the BJP and their persistent demand for withdrawal of article 370. That also contributed to the further alienation of the Kashmiri people. What have we gained? What has the country gained by he farcial hoisting of national flag in Jammu & Kashmir with the complete protection and help of the Indian Army? It has further enraged the people. On the one side, they are disgusted with the terrorists and on the other, they are terrorised by their actions and they got further alienated. The opportunity for improv-

[Shri Sukomal Sen]

ing the situation was thwarted by these actions. Article 370 was sought to be withdrawn, persistent demand was made. Kashmiri people are terrorised. They got frightened. If article 370 goes, what then remains? The autonomy that they enjoyed will go with the abolition of article 370. It has contributed to the furher deterioration of the situation. In this situation, while you are drifing and the Government of India is grouping in the dark without a political initiative, Pakistan has succeeded in internationalising the issue. At least in the Organisation of Islamic Countries they could get a resolution passed in their favour. Even in European Parliament they got a resolution passed, though many members abstained and some voted against it. Even America and Egypt wanted an immediate solution to the Kashmir issue. But Pakistan got international support from various countries. They have succeeded in internationalising the issue and the Government of India simply drifted. Now, Sir, in this situation, I would suggest that the Government of India should take a realistic view. They should try for a political settlement, a political settlement of the whole issue. Things cannot be settled by merely sending the army or para-military forces. People cannot be won only by application of force by military and paramilitary forces. I feel that—it is our party's view—on the basis of the concept of autonomy the Kashmir problem should be settled. Attemps should be made to have a political negotiation with persons who are prepared to negotiate. The Government must find out who are ready to negotiate. The Government of India should be prepared to give more autonomy to the Kashmir people instead of withdrawing Article 370, they should be given more autonomy so that the identify of the Kashmiri people is properly safeguarded. The Kashmiri people should think that their culture and their identity as the Kashmiri people are properly portected and the economy of the Kashmiri people is developing. Some developmental work should start there. The people in Kashmir should feel that the Government of India is doing something for the development of Kashmir's industry and other sectors of the economy. Unless that is done, nothing will happen. At this moment elections will be worse than in Punjab. It will further alienate the people. It will give further handle to the terrorists, further handle to Pakistan. I would like to conclude by saying that the Government should pay attention in respect of Jammu and Ladakh also. Some sort of decentralisation of power should be there for the regions of Jammu and Ladakh because there is also a feeling of alienation. Some slogans have been raised, some demands have been raised for separation of Ladakh, for separation of Jammu. That should be thwarted. That can be thwarted only by decentralisation of powers, by giving certain type of autonomy to Ladakh and Jammu regions so that they don't feel alienated. At the same time, I would also like to draw the attention of the Government to the plight of migrants. Not only Hindus but thousands and thousands of Muslims have also migrated who would not subscribe to the views of the terrorists. What is their position? They are in a miserable condition. Anybody visiting Jammu city can find the plight of those migrants living on the footpaths. Even in Delhi, many of them have been provided with stalls, some shanties on footpaths and similar other places. They are not provided with proper shelter, jobs and academic facilities for their children. The Government should look into it. Now about the employees. The Kashmir Government employees are badly treated. Only three months back there was a strike—I am not mentioning about Kashmir—there the employees went on strike at the behest of terrorists. Why did the

employees of Jammu go on strike for two weeks? They were lathi-charged. Many of them have been arrested on economic issues. That too was not accepted by the Government. This is how the Government is treating the employees. If we really want Kashmir to develop and alienation should go, then Government should pay attention to all these aspects. I would say that I am not prepared to forego the rights of Parliament to confer the same on the President of India. If necessary, Parliament session should be extended or a special session should be called so that all necessary enactments go through Parliament and the Members of Parliament can attend to them and give a thought to them. So, I strongly oppose this Bill and request the Government to take full initiative and try to settle the problem of Kashmir.

चौधरी हरी सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन में जम्मू-कश्मीर लेजिस्लेचर (डेलिगेशन आफ पावर) बिल, 1991 पर चर्चा हो रही है । यह बिल समय के बड़े अनुकूल परिस्थितियों में, समय के मुताबिक आया है। इसकी जो आवश्यकता है वह भी बहुत ही मुनासिब है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 18 जुलाई को इसकी अवधि समाप्त हो जायेगी । ये जो प्राविजन इस बिल के द्वारा लाये गये हैं इनको पारित न किया जाय तो राष्ट्र के सामने और राज्य के सामने बड़ा संकट पैदा हो जायेगा । इसलिये जैसा मैंने कहा, यह बहुत मुनासिब है।

यह बिल कानून सम्मत, संविधान सम्मत और सभी कानूनी पहलुओं से बिल्कुल उचित है और इसको पास किया जाना बहुत सही है । इसमें हमारे साथियों, श्री भंडारे जी ने और श्री मदन भाटिया जी ने कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। वे कानून के ज्ञाता हैं और प्रेक्टिसिंग लौइयर्स हैं। उन्होंने तफसील से इन सारी बातों पर प्रकाश डाला है । मैं उन सारी बातों में दुबारा जाकर सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं । उन्होंने तफसील से सारी बातें बता दी हैं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) पीठासीन हुए]

यह बिल परिस्थितियों के अनुकूल है। अभी काश्मीर के अन्दर और खासतौर पर वैली के अन्दर एक विशेष परिस्थिति है और गंभीर समस्या है। वह प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर है । पड़ौसी देशों की सीमा उससे लगी हुई है। उससे संबंधित कितने ही मसले सदन के समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं । इन सारी परिस्थितियों को देखते हुये यह कानून बनाना बहुत आवश्यक है । दूसरा इसका विकल्प वहां चुनाव भी हो सकते हैं जिससे एसेम्बली कायम की जा सके। लेकिन जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर चुनाव कराये जाने चाहिये । आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां भी रही है, हमने हमेशा चुनावों को पसन्द किया है । आपके सामने पंजाब का जीता जागता नमूना है । वहां पर भंयकर परिस्थिति होते हुये भी चुनाव कराये गये । आज वहां पर एसेम्बली काम कर रही है और संसद में लोग चुन कर आये हैं और इस सदन में भी आये हैं । कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हक में रही है। लेकिन हालात को देखना पड़ता है। मौजूदा हालत में काश्मीर में चुनाव करना उचित नहीं है । यह समय की पुकार है कि इस वक्त वहां की हालत को देखते हुये चुनाव कराना ठीक नहीं है । हमारे होम मिनिस्टर साहब, केन्द्रीय सरकार और मंत्रीगण वक्त पर पर प्रयत्नशील रहते हैं कि चुनाव करा दिये जायें । लेकिन काश्मीर में स्थिति का जायजा लेकर इस समय चुनाव करना उचित नहीं है। मैं भी इस स्थिति का हामी हूं ।

आप यह भी जानते हैं कि हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान के अन्दर पांच सौ ऐसे सेन्टर्स हैं जहां पर टेरोरिस्ट्स को

[चौधरी हरी सिंह]

ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान हिन्दुस्तान के खिलाफ रहता है। टेरोरिस्टों को भड़काता है, उनको हथियार देता है और आर्थिक सहायता पहुंचाता है। वह भारत के अन्दर बेचैनी और डिसआर्डर पैदा करता है। अभी तक वह अफगानिस्तान से उलझा हुआ था। अब वहां से भी उसका ध्यान हट गया है। अफगानिस्तान में उसको क्या सफलता मिली, इसमें इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अब वह पूरी तरह से हिन्दुस्तान में खराब हालत पैदा करने में लग गया है। पाकिस्तान की अन्दरूनी हालत खराब है। सिंध प्रदेश पाकिस्तान से अलग होने की स्थिति में आ गया है। वहां पर बिलकुल मिलिटरी रूल है। वहां पर मुहाजिबों को कदम कदम पर दबाया जा रहा है और सिंधियों को गिरफ्तार करके ददाया जा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, उनका मर्डर किया जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। वहां पर जब भी कोई क्राइसेस पैदा होता है तो हिन्दुस्तान में आतंकवादियों का भड़काया जाता है, उनको ट्रेनिंग और हथियार देकर हिन्दुस्तान में भेजा जाता है। पाकिस्तान ने अब एक दूसरा नजरिया भी अख्तियार कर लिया है। वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ह्यूमन राइट्स के जरिए यह कहता है कि पंजाब के अन्दर और काश्मीर के अन्दर भारत सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है, बच्चों को मार रही है। इस प्रकार से हिन्दुस्तान की तस्वीर वह दुनिया में खराब करना चाहता है। अब पाकिस्तान ने यह एक नया फ्रन्ट खोल दिया है जो सच्चाई से परे है और झूठ से भरा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड में एक साहब हैं जो ह्यूमन राइट्स के नाम से सैकड़ों की तादाद में कैंप लगा रहे हैं और वहां पर पोस्टर लगाते हैं, किताबें देते हैं, पफलेट्स देते हैं, दस्तखत कराते हैं कि हम यू.एन.ओ. को भेजेंगे, हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। ये चीजें हिन्दुस्तान की सारी तस्वीर को खराब कर रही हैं। इसी के साथ-साथ यह भी है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान की तस्वीर को खराब करने के लिये, दुनिया में इस तरह के प्रचार के लिए उसने एक मोर्चा शुरू किया है। भारत सरकार को इससे सतर्क होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर, एसोसियेशन बनाकर सारे मुल्कों में हमारी तस्वीर खराब कर रहे हैं। यह कार्य क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका की सीनेट के अंदर एक बिल लाया गया है कि अगर वे अपने यहां ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें अधिक सहायता नहीं दी जायेगी। इस तरह का वायदा उनसे लेने के लिए कहा गया है और वहां पर इस तरह का बिल आया है। श्रीमन्, यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। वह आर्थिक तौर पर भी भारत को लंगड़ा करना चाहता है, बदनाम करना चाहता है और जो इस्लामी मुल्क हैं, उनसे हमारी दोस्ती खत्म कराना चाहता है। इसलिए भारत सरकार को इस बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही सचेत रहना चाहिए। ... (**समय की घंटी**)

माननीय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं, यह समय के बड़े ही अनुकूल है। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, दुनिया की कोई भी ताकत इसको हमसे अलग नहीं कर सकती। लेकिन जो विधेयक गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है "जम्मू और कश्मीर विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992", इसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जम्मू और कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने में इससे सहायता मिलेगी। क्योंकि जितने भी अधिनियम हैं या कानून हैं, उनको बनाने का अधिकार इस देश की संसद को है और इसके उद्देश्यों और कारणों में गृह मंत्री जी ने कहा है कि :

"There are a number of amendments to various State enactments made during the Governor's Rule of the State whose validity is due to expire in July, 1992."

उनके भाषण से पता लगा कि उनको 18 जुलाई, 1992 तक कानून बन जाना चाहिए ।

"Because of the large number of such enactments involved it may not be possible for Parliament to find sufficient time to enact the same."

मैंने जैकब साहब से इस बारे में पूछा भी था । उन्होंने उत्तर दिया कि 11 ऐसे विधेयक हैं जो लंबित हैं। लेकिन किसने रोक रखा था इस सरकार को 8 जुलाई से पहले ऐसा करने को ? इसके लिये संसद का एक स्पेशल सेशन भी हो सकता था, इन 11 विधेयकों को पास कराने के लिए । सरकार को यह समझ लेना कि संसद के पास इन विधेयकों को पास करने के लिए समय नहीं है, यह संसद के अधिकारों का अतिक्रमण है और संसद के अधिकारों पर कुठाराघात है । सरकार को जानकारी थी कि 11 विधेयक हैं और उनको संसद से पारित कराना आवश्यक है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी कठिनाई थी, कौन सी ऐसी दिक्कत थी जो 8 जुलाई से पहले संसद को बुलाकर इन 11 विधेयकों को पारित नहीं किया गया ? राष्ट्रपति इस देश की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति है लेकिन घूम-फिरकर वह एक ही व्यक्ति है और उनको वह अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए जो इस देश की संसद के अधिकार हैं। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि संविधान के अनुच्छेद 357 के सब क्लाज (1) में इस बात का अधिकार है और इसके अन्तर्गत यह विधेयक लाया गया है। लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं थीं जो इस प्रकार का विधेयक लाने की आवश्यकता हुई । आज जम्मू और कश्मीर में जनता द्वारा निर्वाचित संसद सदस्य लोकसभा में नहीं हैं, जम्मू और काश्मीर में विधान सभा नहीं है । जम्मू और कश्मीर में करीब करीब 15 या 20 वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए । 1991 में सारे देश में जन-गणना हुई लेकिन जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई । आखिर क्या वजह है जो सरकार एक के बाद दूसरा ऐसा कदम उठाती जा रही है जिससे जम्मू और कश्मीर में लोगों को इस बात की आशंका हो रही है कि उनको देश की मुख्य धारा से अलग रखने का प्रयास किया जा रहा है । इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, हम आज भी बैठ सकते हैं, कल बैठ सकते हैं, 17 तारीख को बैठ सकते हैं और 18 तारीख को भी बैठ सकते हैं, इन 4-5 दिनों में, जैसा कि श्री सुकोमल सेन जी कह रहे थे, सदन को बिठाकर, बाकी सारे कामों को टालकर ये जो 11 विधेयक हैं, इनको पारित किया जाये। जम्मू और कश्मीर में तीन हिस्से हैं । एक है जम्मू और दूसरा वेली श्रीनगर वाला हिस्सा और तीसरा है लद्दाख । लद्दाख के लोगों की मांग है कि जैसे कश्मीर का और हिस्सा पिछड़ा हुआ है, लद्दाख और भी पिछड़ा हुआ है । वहां पर शिक्षा के साधन नहीं हैं, सड़कों के साधन नहीं हैं, रोजगार के साधन नहीं हैं । वहां के जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन लद्दाख के हैं, उन लोगों ने भारत सरकार के पास एक मांग पत्र भी दे रखा है । वहां पर एक आन्दोलन क्षेत्रीय विषमता के खिलाफ, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, आवागमन के साधन उपलब्ध कराने के लिए चल रहा है। मैं यह जरूर चाहूंगा कि लद्दाख के बौद्ध संघ का जो मांग पत्र भारत सरकार के पास आया है, उसके संबंध में सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए । वहां पर एक आन्दोलन चल रहा है, यह बात पिछले सत्र में भी उठाई जा चुकी है । इसलिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहियें ।

दूसरा, जम्मू में शरणार्थी हैं । माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 15000 परिवार ऐसे हैं जो जम्मू-कश्मीर से आ कर के दिल्ली में बसे हुए हैं । आखिर क्या वजह है ? जम्मू में भी ऐसे लाखों परिवार होंगे । इसलिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहियें । जितने भी लोग शरणार्थी के नाम से दिल्ली में आ कर बस गये हैं, जम्मू में आ गये हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यह भी कहा कि इनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए ताकि यह लोग अपने प्रदेश में वापिस जा सकें । इस सिलसिले

[श्री सत्व प्रकाश मालवीय]

में भारत सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिएं ।

मैं भी इस बात को मानता हूं कि वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव हो सकें । लेकिन कम से कम भारत सरकार को इस प्रकार की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए । वहां पर एक ऐसा राजनैतिक माहौल बने जिससे वहां के लोग यह समझें कि प्रदेश के शासन में, हकूमत में उनकी भी भागीदारी है । वहां पर एक सलाहकार परिषद् बनी है । करीब दो तीन माह पूर्व वहां के राज्यपाल ने एक सलाहकार परिषद् का गठन किया । मेरी जानकारी यह है कि जब से यह सलाहकार परिषद् बनी है केवल एक बार उसकी बैठक हुई है । उसके बाद उसकी बैठक ही नहीं हुई । बहुत से राजनैतिक दलों ने इस बात की मांग को रखा कि उनके दलों का भी इस सलाहकार परिषद् में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । इस विषय पर मैंने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । मेरी जानकारी के अनुसार यह सलाहकार परिषद् रेप्रेजेंटेटिव नहीं है, सभी राजनीतिक दलों की उस में हिस्सेदारी नहीं है, इसकी बैठक भी नहीं होती है । मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के सुझाव का समर्थन करता हूं । अगर यह विधेयक को वापिस नहीं लेते हैं तो उन्होंने जो सुझाव रखा है कंसलटेटिव कमेटी के सिलसिले में एक तो राष्ट्रपति महोदय के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है --

"Provided that before enacting any such Act, the President shall, whenever he considers it practicable to do so, to consult the Committee."

यह आवश्यक नहीं होगा राष्ट्रपति जी के लिए जो कंसलटेटिव कमेटी बनाई जा रही है, उसकी सलाह लेना । पर उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है । अगर राष्ट्रपति जी उचित समझेंगे, तो कंसलटेटिव कमेटी की सलाह लेंगे । पंजाब की जो कंसलटेटिव कमेटी है, उसके बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, क्योंकि उस कंसलटेटिव कमेटी का मैं खुद भी सदस्य था । एक बार भी उसकी बैठक नहीं हुई । इसलिये जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सुझाव दिया है कि पार्लियामेंट की एक स्टेंडिंग कमेटी बनाई जाये और पार्लियामेंट की वह स्टेंडिंग कमेटी फैसला ले कि कौन-कौन से विधेयक वहां के लिये आवश्यक है, और वही विधेयक पारित किये जायें । इन शब्दों के साथ मैं फिर गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा ये इस विधेयक को वापिस लेने की कृपा करें और अगर वह कृपा नहीं करेंगे तो हम लोग पूरी ताकत के साथ इस विधेयक का विरोध करेंगे ।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill, The Jammu and Kashmir Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1992, to confer on the President the power of the Legislature of the State Government of Jammu and Kashmir to make laws. Sir, though it has been said that these powers are to be conferred on the President to make laws, what I am given to understand is that these powers are only to extend the laws already made from the time of the Governor's Rule and the President's Rule in that State. I think it will not be proper for this House to usurp the powers of the people of Jammu and Kashmir. So, in that sense, I feel this House or the Committee which will be appointed by the President, will not go into the rights of the people of that State to form laws, as that right should vest in them as and when the Assembly is constituted in that State. Sir, the people of Jammu and Kashmir have been the victims of terrorism and secessionist forces. Again, that State has been a casualty at the alter of democracy because Governor's Rule was imposed for some political reason and, after six months, we had no option but impose the President's Rule for two years under article 356. tI was painful for the whole nation to impose President's Rule because we felt that Jammu and Kashmir has a peculia rposition in the Constitution of India since we

have a special provision under article 370 for that State in our Constitution. As rightly mentioned by my colleague, Shri Bhandare, and as we all know, in the history of our Independence, this was the last State to accede to the Indian Union. The people there had some reservation in the beginning, and that posed a problem. But we had to make them feel at home and make them merge with and integrate themselves with the national mainstream.

Sir, this Bill only confers some powers on the President as, under article 356 of the Constitution, the President may usurp all the powers within the State conferred upon the Government except the powers of the judiciary and the legislature. Under article 357, Parliament, by an Act, may delegate this power to the President. I am happy to see in this Bill under clause 3(2) wherein it is said that the President would consult a Committee consisting of the Members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha in the ratio of 2:1. Again it is going to be a mini-Parliament to advise the President. It has been mentioned that the President may, whenever it is practicable to do so, consult the Committee. But I would like to suggest that the Home Minister must come up with a written provision to see that it is mandatory on the part of this Committee to advise the President because it is the voice of the people.

Secondly, Sir, as we have no elected Members in the Lok Sabha, though we have two Members in the Rajya Sabha, from the State of Jammu and Kashmir, I think it would be appropriate also to call the ex-MPs as special invitees since they represented the people in the past. They may be invited since no Member is there from that State in the Lok Sabha due to certain technicalities. I think it will be appropriate on the part of the Home Minister to include these ex-PMs in the subsequent notification.

Sir, this House has been debating certain issues such as the Securities Scam, the Ayodhya issue, etc. We have to pass this Bill in order to extend the Acts, before 17th July, 1992, which have existed in that State and whose validity is expiring. I feel that there is no harm in delegating these powers to the President. At the same time, I feel that the Central Government should make attempts—and I am confident that the attempts are still on—to talk to the people. The other day we saw the Home Minister visiting that State and having a dialogue with the people there and he also mentioned that there was a turning point in the attitude of the people and that the people would like to come back to the mainstream and see that progress and development are there in the State and that democracy is revitalised.

Sir, despite many odds this Government held the elections in Punjab and we know that we have an elected Assembly there, we have the Members in the Lok Sabha and also in the Rajya Sabha. It was painful to see during the current Presidential and Vice-Presidential elections that Jammu and Kashmir is the only State which does not have full representation in the electoral college to elect the President and the Vice-President of India. It is not a healthy trend in a democracy. So, I think that the Government should take some initiative and see that the election to the Assembly is completed at least before the election of the Vice-President.

With these few words, Sir, I support this Bill and I feel that whatever suggestions I have made, which are not incorporated in the Bill, will be looked into by the Government. Thank you, Sir.

डा० जैड० ए० अहमद (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और डट कर विरोध करूंगा। कुछ और लोगों ने भी

[डा० जैड० ए० अहमद]

विरोध किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया। लेकिन जिस आधार पर उन्होंने विरोध किया, मैं उस आधार पर इसका विरोध नहीं करना चाहता। मेरा आधार तो साफ है।

मैं एक मामला आपके सामने पेश करूंगा, एक प्रश्न पेश करूंगा। क्या यह बिल काश्मीर के लोगों को हिन्दुस्तान के ज्यादा नजदीक लाएगा या दूर ले जाएगा? मेरी राय यह है कि वहां अब यह चर्चा होगी कि जबरदस्त दमन आने वाला है। यहां तो कह दिया हमारे कांग्रेस के भाइयों ने कि एग्रेशन वाई पाकिस्तान हो गया। यहां कांग्रेस के एक भाई ने कहा कि स्टेट आफ वार पाकिस्तान से शुरू हो गयी। अब स्टेट आफ वार का मुकाबला करने के लिये आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्या। आप भी स्टेट आफ वार—वह हालात पैदा करके कर रहे हैं कि तानाशाही शासन के सुपुर्द पूरी चीज कर दी जाये। पार्लियामेंट, को छोड़ दिया जाये, एक व्यक्ति के एक फर्द के सुपुर्द कर दिया जाये—काश्मीर की किस्मत वह फर्द तय करेगी और वह कौन? प्रेजीडेंट आफ इंडिया का बड़ा नाम है। वह हमारे लिये—भगवान के बाद वहीं है पोलिटिकली, लेकिन यह काम यह नौकरशाही करेगी। यह सेक्रेट्रीज, डिप्टी सेक्रेट्रीज गवर्नर्ज वह तय करेंगे कि इंटरवेंशन किस तरह से हो और यह जो आपने उसके ऊपर मुलम्मा बढ़ाया है कि एक कमेटी बना दी जाएगा जो उस पर गौर करेगी—कुछ नहीं होगा, यह सब कुछ नहीं होगा। बड़े-बड़े अफसर बैठेंगे, जिनके सामने कोई हिन्दुस्तान की एकता का नजरिया नहीं है, पावर का एक्सरसाईज करो, आर्मी बैठेगी और भी बैठेंगे और डट कर के पिटाई करो। यह होने वाला नहीं है। समझ लो, कंसट्रेक्शन आफ पावर जहां होता है, वहां यही होता है। जहां डेमोक्रेटिक एलिमेंट को, डेमोक्रेटिक अंसर को कश्मीर कमजोर कर दिया जाता है, वहां पर यह तानाशाह सब आ जाते हैं। मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा, गवर्नर आफटर गवर्नर बदला गया है और सबकी नीयत यही थी कि डट कर इनका मुकाबला करे, पिटाई करो, तब ठीक होगा।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : यह तो अच्छा नहीं कहा उसने कि पिटाई करो।

डा० जैड० ए० अहमद : उसने तो बहुत पिटाई करवायी। उसने तो लाश वहां फिकवा दी, गोली चलवाई, बेचारे मीर वास की लाश को नदी में फिकवा दिया। तो यह न कहिये कि कोई अच्छा काम है या बुरा काम है। मैं यहां पर कोई कंपैरीजन नहीं करना चाहता, न किसी का नाम लेना चाहता हूं। किसी ने कहा कि पीटो, ठीक हो जायेगा, यह थक जाएगा, जायेंगे। कब तक यह चलायेंगे?

हम जानते हैं कि ऐसे जब कौमी जज्बात किसी फंडामेंटेलिस्ट नजरिये को लेकर, चाहे वह नजरिया हिन्दू नजरिया हो, मुसलमान नजरिया हो, सिख नजरिया हो, अगर वह फंडामेंटेलिस्ट नजरिया है, तो फिर वह आहिस्ता से दबता नहीं है, आहिस्ता से नहीं दबेगा। सिखों को दबा पाये। भारतीय जनता पार्टी ने शोर मचाया कि हिंदू राष्ट्र होगा, राम राज्य होगा।

अब कांग्रेस कांपती है कि इनका मुकाबला हम कैसे करें। इन्होंने तो रट पकड़ ली... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : इसीलिए यह आपका सहयोग चाहते हैं।

डा० जैड० ए० अहमद : वह तो देखिये कि किसका सहयोग कौन लेता है। इसी तरह जब मुसलमान फंडामेंटेलिस्ट आइडियाज को लेकर उठ जाता है, तो उसको दबाना बहुत-बहुत मुश्किल है। (समय की घंटी) इसलिए यह मसला आसानी से हल नहीं होगा।

मैं चाहता हूं कि आप इस बिल को बिदड़ा कर लीजिए और सोचें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इतने दिन सो रहे थे कि यकायक आप कहते हैं कि ग्यारह बिल हमारे पड़े हैं। पहले नहीं ख्याल आया था हाय कश्मीर, हाय कश्मीर, हाय कश्मीर की बात

5.00 PM

सिर्फ 11 बिल आप पास नहीं करवा सकते थे। अब आप कहते हैं जल्दी-जल्दी सब हल हो जाएगा। प्रेसीडेंट को सुपुर्द कर दो। प्रेसीडेंट का मतलब नौकरशाही है। उसको सुपुर्द कर दो। इस बिल को आप रोकिए, यह बिल बहुत पेचीदगी आपके लिए पैदा करेगा और काश्मीर के अन्दर हालत ज्यादा खराब हो जाएगी, खास तौर से मुसलमानों के लिए। इसलिए चूंकि अब घंटी बज गई है, मैं इस बिल को ओपोज करता हूं। मेरी पार्टी भी ओपोज करती है और हम डट कर ओपोज करते हैं। नंबर दो, मैं यह चाहता हूं जहां तक इलैक्शन का सवाल है आप आहिस्ता-आहिस्ता कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इनीशिएट कीजिए, कुछ बात-चीत शुरू कीजिए। जैसे आपने कहा कि पोलिटीकल इनीशिएटिव लीजिए, पोलिटीकल इनीशिएटिव लेते नहीं और ऊपर से तानाशाही का जो शिकंजा है उसको मजबूत करते जाते हैं। जनता के सहयोग की कोई बात नहीं। अब एक फुलझड़ी और छेड़ दी कि साहब, अभी तो हम इलैक्शन करवायेंगे। आप इलैक्शन के लिए कुछ माहोल पैदा करो। इलैक्शन होगा और होना चाहिए। मैं इससे इतफाक करता हूं कि बिल्कुल इलैक्शन के जरिए ही होगा, न प्रसीडेंट रूल कुछ करेगा और न कुछ और रूल काम करेगा, अल्टीमेटली इलैक्शन ही होगा और उसके लिए तैयारी करो। आज कितनी इकोनोमिक हालत वहां खराब है। यूथ उजड़ गया है। दिखाने के लिए ही सही 5–6 हजार वहां के यंगमैन को यहां से नौकरी दे दी। वहां डिवैलपमेंट प्रोजक्ट्स खत्म हो गए हैं, वह शुरू करो। डिवलपमेंट कुछ इकोनोमिक एड की शक्ल में काश्मीर को दो काश्मीर के डिवलपमेंट का सोचो और कुछ पैसा खर्च करो। अरबों रुपया खर्च हो रहा है, चारों तरफ से लूट रहा है। काश्मीर तो रहेगा और काश्मीर नहीं रहेगा यह गलत बात है। यह बड़ी-घड़ी कहना वह हमारा अंग है। आपका नहीं है, उसका दिल-दिमाग दूर हो गया है। वह पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। जरूर करेगा। यह आपकी कमजोरी है। आपकी 40 साल की डांवाडोल नीति काश्मीर की है। काश्मीर के अंदर प्रोजैक्ट्स नहीं डिवलप हुए। काश्मीर पिछड़ा हुआ प्रदेश है, सूबा है। अब जहां 40 साल राजनीति न हो डमोक्रसी न हो, डिवैलपमेंट न हों, जहां खाली फंडामेंटलिजम उभरे, पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म उभरे, उन दोनों का मुकाबला हो जाए, आप बैठे ताक रहे हैं, देख रहे हैं और यह बात मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान ने कोई जादू कर दिया। यदि है तो आप क्या कर रहे थे। अगर पाकिस्तान ने जादू कर दिया और सब ले लिया तो तुम्हारी कमजोरी है। यहां अब फंडामेंटल फोर्सेस बढ रहे हैं, उसको आपने बढने दिया। अगर एक काश्मीरी कहता है कि मेरी बाबरी मस्जिद गिर रही है, गिराई जाएगी और हिन्दुस्तान कहता है कि मैं यूं ही बैठा रहूंगा तो मेरी मस्जिदें फिर गिराई जायेंगी, और गिराई जायेंगी, पाकिस्तान कहता है हां, जरूर गिराई जायेंगी। पाकिस्तान जरूर कहता है कि जरूर गिराई जायेंगी तुम्हारे यहां कोई मस्जिद नहीं रहेगी। तो फंडामेंटलिज्म अगर हिन्दुस्तान में पनपता है पाकिस्तान में पनपता है तो काश्मीर का मसला कैसे हल हो सकता है? हमारी कौमी सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से इस मसले को हल करना है, तानाशाही तरीके से नहीं चलेगा, पावर का कंसेंट्रेशन करके नहीं चलेगा।"

बस अब और मैं कुछ नहीं कहता चुनाव होगा, होगा, आएगा और चुनाव के लिए तैयारी करिए और चुनाव की तैयारी की बात करिए। लोगों को बताना चाहिए एसोशिएट करना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता यकायक पूरे प्रदेश में चुनाव करायें या नहीं आप शुरू करो जिला लैवल पर उससे नीचे लैवल से शुरू करो कहीं तो एसोसिएट लोगों को करो। लोगों में कंफीडेंस पैदा हो कि हां हमारी भी ली जाती है। इसके लिए कमेटियां बनायें और उसमें लोगों को एसोसिएट करें। छोटे-छोटे चुनाव करो ताकि चुनाव की तरफ लोगों का दिमाग जाए, कत्लो-गारत की तरफ नहीं। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं साहब, रिफ्यूजी जो बहुत से आए हैं और भी है, मैं अपने आपको इसके साथ एसोसिएट करता हूं। बिचारों की बहुत बुरी हालत है, तबाह हो रहे हैं। उसमें हिन्दू ज्यादा हैं,

[डा० जेड० ए० अहमद]

मुसलमान कम है। लेकिन हैं दोनों और तबाह दोनों हो रहे हैं। इसलिए अरबों रुपया जो इधर-उधर खर्च किया जाता है, तो उनको कुछ और सहायता दी जाए उनको बसाया जाए। इस तरफ मैं गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहता हूं।

जहां तक जम्मू का सवाल है जम्मू, अपनी जगह पर है। जम्मू के लोग कहते हैं कि यहां तो सेंसस ही नहीं हुई है। हम कितने हैं—4 लाख हैं, 5 लाख हैं, कोई पता नहीं है। इस तरफ भी मैं गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहता हूं। इतनी बात कहकर मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम : लद्दाख के बारे में भी कुछ कहिए।

डा० जेड० ए० अहमद : लद्दाख के बारे में मैं नहीं जानता।

श्री संघ प्रिय गौतम : लद्दाख में तो बोद्धों की महिलाओं के साथ शादी कर के वैली के लोग धर्मान्तरण कर रहे हैं।

डा० जेड० ए० अहमद : वह मुझे मालूम नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : गौतम जी बीच में नहीं बोलिए।

डा० जेड० ए० अहमद : मैं एक बात की तरफ और गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहता हूं। जम्मू शहर को "सी" कैटेगरी में लोअर कैटगरी में डाला गया है। अगर वहां सेंसस होता तो वह "बी" कैटगरी में चला जाता। इसलिए मेहरबानी कर के उस शहर की तरफ भी ध्यान दीजिए। वहां इतने लोग दौड़-दोड़कर पहुंच गए हैं। वहां पापुलेशन बढ़ गई है। इसलिए जम्मू को हायर कैटेगरी में रखा जाना चाहिए और इस संबंध में जो कदम उठाने हों वह आप उठाइए शुक्रिया।

*SHRI JAGIR SINGH DARD (Punjab): Mr. Vice-Chairman, I would like to draw your attention to some historical facts. During the regime of Aurangzeb, many upheavals took place and Hindus were converted into Muslims. A stage reached when Kashmiri Muslims approached Maharaja Ranbir Singh and told him that they knew the fact that their ancesters were Hindus and expressed their desire to become Hindus. The Maharaja acceded to their request. But there are communal as well as secular elements in every community. About 100—200 Brahmins went to the Maharaja and told him that they won't permit it at any cost and threatened to commit suicide. Thus, the matter ended there.

Mr. Vice-Chairman, if that offer had materialised, we would not have had the problem of Kashmir before us as it is today. This problem is the creation of those funadmentalist Brahmins. Not only that. There was a prince in Bengal known as Kaala Pahaar. He wanted to marry a Muslim girl. But the Brahmins declared that the marriage could not be solemnised and said that an inter-caste marriage could not take place. The girl offered to embrace the Hindu religion but the Brahmins did not permit even that course. Consequently, the prince get himself converted as a Muslim and all his supporters also became Muslims.

The problem of Bengal started from that very point. If the fundamentalists had not created this problem, India could not have been divided. We could not become a Nation. Why could we not become a Nation? Lord Manu handed down a law which divided the country into four Varnas, namely, Vaishyas, Shudras, Kashatriyas and Brahmins. When the Muslims later came into our country, they were also categorised as Shudras.

*English translation of original speech delivered in Punjabi.

They were sore that they hoisted the Flag at Red Fort but still they were being treated as Shudras. As a result, the country was partitioned, lakhs of people became homeless, lakhs of people were killed and women were molested.

I, therefore, feel that Fundamentalism—be it Hindu, Sikh or Muslim Fundamentalism—must be crushed with a strong hard. Mustafa Kamaal Paasha of Turkey was the only person who completely uprooted fundamentalism. Our country, today, needs a courageous man like him who can fight communalism.

The issue of Pakistan is quite simple. Both the countries possess modern weapons. If a war breaks out, both the Punjabs will be destroyed and neither of the two Punjabs will survive. But I think we canot do without them. What to do under such circumstances? This August House will have to reflect on this aspect of the problem.

Jai Hind.

[**The Deputy Chairman** in the Chair]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jagmohan. Mr. Jagmohan, I do not want to disturb you while speaking but today this Bill has to be sent back within 15 minutes.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): If it is not sent back, what will happen? If we defeat this Bill on the floor of this House....

THE DEPUTY CHAIRMAN: That you won't do, I know.

SHRI DIPEN GHOSH: How are you taking it for granted that this Bill will be sent back?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know, Mr Dipen Ghosh, that you will not do that. You understand the seriousness of the situation. You are a responsible Member of this House. So, we have to send it before 5.30.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): When he says we will defeat it, whom is he representing ? Is he representing the BJP, himself or....

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is an institution in himself. Now, may I ask Mr. Jagmohan to make his contribution?

SHRI JAGMOHAN (Nominated): May I know what is the t ime which you would like to give me?

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are 7 minutes for three people. (Interruptions). I cannot help it. It was defided to have two hours and you all know how many Members we have in the House. It is not my duty to find out how the time is allotted. (Inerruptions). Now, please, we are cutting into the time of the House. (I nterruptions). No, we cannot do it. I am sitting in the Chair. We have to send it back.

SHRI JAGMOHAN: As indicated by the Chair. I will be as possible. I will only touch a few points. I think a lot has been said for the Bill or aganist it, but what is the basic point ?

Practical necessity is the basic issue. It was in the light of the practical necessity that these provisions were incroporated mostly by me when I was the Governor because of the situation prevailing at that time. That situation still prevails and it is necessary to continue these provisions. Under the Jammu and Kashmir Constitution, article 92 empowers the Governor to make these laws, changes, because the legislative powers rest with the Governor during the Governor's rule and now they are intended to be given to the President. In fact, what was enjoyed by the Governor is now being passed on to the President in pratical terms.

The other aspect is, what are these laws? Say, the Public Safety Act Why did I amend it ? I amended it on the ground that there was a large-scale violence, people and terrorists were going acorss the border. The Government had totally collapsed. There was no rule, no intelligence agency. There was total internal subversion. Even the warrants were not being issued by the District Magistrates. The Advocate General was not appearing in the court and the people were breaking the jails and

[Shri Jagmohan]

escaping. So, we had to provide for detention outside the State also. So, it was not that some liberty was taken or it was not something that the Parliament would not have normally approved. These are due to practical necessity. At that time there was a total collapse of the authority and it was done to restore that authority which had collapsed due to internal subversion and total lawlessness. Therefore, certain actions had to be taken and these were very minor amendments from that point of view. Since all of us recognise that the problem of terrorism and subversion still persists, the continuance of these laws is in the interest of the nation.

The other aspect which I would like to point out is, unfortunately there has been a shift in policy. A remark was made that the Assembly was dissolved. The basic issue is, the conditions at that time were such that you had to take back the reigns of power with minimum of casualties and it was absolutely necessary to dissolve the Assembly so that you could take very strong action against the pro-Pakistani elements, or Pakistani elements or those who were internally subverting in tht State of Jammu and Kashmir, and at the same time giving a line of retreat to the moderate elements within the terrorists militants. Unless that line of retreat was given, the number of casualties would have been much higher...(Interrupions)... I was able to wrest back the power with less than 100 casualties, and the dissolution was necessary for doing it. Another basic point is that you should have a ground control. In November, 1989 the elections were held and we saw that not more than one per cent came to vote. You have to accept the practical realities, even now.

First we have to establish the ground authority. This fact was not recognized and my critics unnecessarily blamed me. But the basic issue is, today, even after 2-1/2 years, I am asserting that unless you establish authority on the ground, no policy can be changed, no policy can be introduced. Take, for example, a simple thing like this, that the Chief Secretary will be a Kashmiri officer. The moment you announce it or think about it, his son is kidnapped. So, you cannot do anything unless you establish authority on the ground, not even minor policy change. What is to be done is that you have to show a very strong hand, so far as the pro-Pakistan militants are concerned.

What is happening now? The ex-Chief Justice of Jammu and Kashmir or Sikkim High Court is filing affidavits in the courts, just copying Pakistani leaflets and saying, on affidavit, that India has annexed Kashmir by force, fraud and deceipt, and his pamphlets are being reproduced in the United States and the UK, saying what the ex-Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court says. And the Government does not prosecution him for sediiton. What signals are we giving to the people? I have got the whole writ petition. If you read it, it is astounding. And yet the Government has not acted Justice Bains has been prosecuted. Why not this gentlemen? It is this type of softness which is preventing us from taking any decision. You can be either hard or soft, you should not fall between two stools. But that is what exactly is happening, you are falling between two stools. About the disinformation...

DR. Z. A. AHMED: What would you prefer?

SHRI JAGMOHAN: You don't give time, you always give me two or three minutes. In any case, I am only suggesting, whenever you have time; it will require more time for me to explain what I want. And this is what I was trying from the very first day.

It was mentioned that I was imposed as a Governor on a Chief Minister who did not want me. And the Chief Minister is on tape having said,

"गवर्नर साहब आप तो पैगम्बर हैं । अगर आज तीन डिब्बे रखे जायें—नेशनल कांफ्रेंस का कांग्रेस का और आपका आपने कश्मीर को इतना जीत लिया है कि आपका डिब्बा भर जायेगा, हमारा खाली हो जायेगा ।' अब कहा जा रहा है कि that gentleman was opposed to me. It was the small interest of certain politicians which made him say so. And why was Benzir Bhutto saying so? Because more than 700 people began to coming to the Raj Bhawan and meeting me. They found that the whole game would be up, whatever the I.S.I. had done for the last two, three years — all their game—would be up. On the one hand it was strong action and also opening a line of retreat for the comparatively moderate elements and, on the other, establishing direct contact with the people and showing the healthy face of India to them, the development face of India to them, the just face of India to them. Then only the solution would have been there. I am quite sure the capital, which was shifted from Jammu to Srinagar, had started functioning and things started improving. Unfortunately, the disinformation compaign went on. Even in this House the newspaper, *The Current*, was displayed, saying, Mr. Jagmohan said "Every Kashmiri is a militant and I will finish everybody, Kashmiri Muslim. I will not leave any militant." Nobody listened to me, nobody defended me in the House, and I had no other option but to file in the High Court a civil damages case against the current man (Editor/Correspondent) to establish myself. There this gentleman goes and says, "Yes, we recognize. He never gave us an interview. We have committed a forgery. We are very sorry for it." Then the Court directs them to publish it in their weekly and they shamefacedly publish it in their weekly. And this is the type of situation in which the nation is being put. When I ever gave ay interview, he puts a interview on the first page with the photograph of o Centrol Minister and myself, and says, "In an exclusive interview Mr. Jagmohan said that he will finish every Kashmiri."

There are many other instances. Since I have only three minutes and I would like to keep discipline. I would request, if you want to listen for a longer period you will have to give me a longer time. Thank you.

उपसभापति : श्री मोहम्मद खलीलुर्रहमान । आपके तो तीन ही मिनट हैं ।

श्री मोहम्मद खलीलुर्रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : कोशिश करूंगा मैडम ।

उपसभापति : इसका बहुत लिमिटेड स्कोप है उसी पर बोल लीजिए । आइंदा बोल लीजिएगा कभी कश्मीर पर ।

श्री मोहम्मद खलीलुर्रहमान : मोहतरम डिप्टी चेयरमैन साहिबा मैं इस बिल की मुखालिफ्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस वजह से कि यह जो बिल है यह जम्हूरियत की स्पिरिट के खिलाफ है । जब किसी रियासत में सदर राज कायम किया जाता है तो उस रियासत की असेंबली के जितने भी अख्तियारात होते हैं वह खुद-ब-खुद आर्टिकल 356 के तहत पार्लियामेंट को आ जाते हैं और जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पूरे हिंदुस्तान के अवाम की नुमाइंदा हाईएस्ट बाडी होती है और ये जो नुमाइंदे होते हैं वह मुख्तलिफ ख्यालात के और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे होते हैं और वह उस रियासत की मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और यह समझ सकते हैं कि कौन सी चीज उस रियासत के मफाद में हो सकती है और कौन सी चीज उस रियासत के मफाद में नहीं हो सकती । मगर एक दफा जब इस पार्लियामेंट के अख्तियारात को राष्ट्रपति को देंगे, इसमें शक नहीं कि राष्ट्रपति की शख्सियत पूरे हिंदुस्तान के लिए और हम सबके लिए एक अजीम शख्सियत है । मगर इसके माने ये नहीं कि पार्लियामेंट के अख्तियारात को सलब कर लिया जाए और वह अख्तियारात राष्ट्रपति को सिर्फ एक शख्स को दिए जाए ।

इससे गलत मिसाल कायम होगी और आजाद हिंदुस्तान की तारीख में इस किस्म की कभी भी कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि पार्लियामेंट के अख्तियारात को सलब करके राष्ट्रपति को दिया जाए । लिहाजा यह एक गलत मिसाल है ।

[श्री मोहम्मद खलीलुर्रहमान]

इससे हटकर दूसरी बात यह है कि इस से कश्मीरियों में भी, मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को पसंद नहीं करेगी कि उनके साथ एक इम्तयाज़ी सलूक किया जा रहा है। पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि पछले 5 साल से मुसलसल सदर राज कायम है और वहां इस किस्म का इम्तयाजी सलूक नहीं किया गया तो फिर क्या वजह है कि जम्मू-कश्मीर के साथ इस किस्म हीं इम्तयाज़ी सलूक किया जा रहा है ! मैं होम मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहूंगा कि आप फरमा रहे हैं कि 11 बिल पेंडिंग हैं। यह किस वजह से पेंडिंग हैं ? क्या पार्लियामेंट को जून के पहले हफ्ते में नहीं बुलाया जा सकता था और इन बिलों को पास नहीं किया जा सकता था ? किसी को भी इसमें एतराज़ नहीं था कि बिल को पास न किया जाए। ऐन वक्त यह बात लाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि वक्त नहीं है, पास कीजिए, आज ही पास कीजिए वरना एक अजीब किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में पैदा हो जायेंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है ? इसकी जिम्मेदार सिर्फ आपकी हुकूमत है। इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं कहूंगा। यह इंतहाई गलत मिसाल है।

पहले से ही कश्मीरी अवाम में कई किस्म के खदशात पाए जाते हैं। सबसे पहले आज उनको यह डर है आर्टिकल 370 के ताल्लुक से, जैसा हमारे बी.जे. पी. के भाई कहते आ रहे हैं कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जाए। आर्टिकल 370 तलवार की तरह उनकी गर्दनों पर लटक रहा है। उससे खुद इन लोगों में बड़ा डर पैदा हो रहा है और उसके बाद अगर फिर इस किस्म के इम्तयाज़ी सलूक अगर करें तो मैं समझता हूं कि वह एतमाद कश्मीरियों का बहाल नहीं होगा बल्कि उनके दिलों में खदशात पैदा होंगे।

लिहाज़ा मैं मरकज़ी हकूमत से यह दरख्वास्त करूंगा कि अभी भी वक्त है, आप इस बिल को वापस कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि बिल के सेक्शन 1 और 2 के तहत आपने कहा है कि एक कंसलटेटिव कमेटी कायम की जाएगी और कंसलटेटिव कमेटी जो कायम की जा रही है पार्लियामेंट की, आपने उसमें कहा है कि 10 लोक सभा के मेंबर होंगे और 5 राज्य सभा के मेंबर होंगे। मगर यह भी मेडंटरी नहीं है। यह भी राष्ट्रपति के डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया गया है। अगर राष्ट्रपति मुनासिब समझें तो इस कमेटी से कंसल्ट करेंगे, अगर मुनासिब न समझें तो कंसल्ट भी नहीं किया जाएगा। मैं आपसे दर- ख्वास्त करूंगा कि–

"Provided that before enacting any such Act, the President shall whenever he considers it practicable to do so,..."

ये लफ्ज़ डिलीट कर दिए जायें और उसको इस तरह से पढ़ा जाए –

"Provided that before enacting any such Act, the President shall consult a Committee contituted for the purpose consisting of 10 members of the House of the People nominated by the Speaker and five Members of the Council of States nominated by the Chairman."

इन सजेशंस के साथ जो वक्त दिया गया है। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

†شری محمد خلیل الرحمن آندھرا پردیش: کوشش کروں گا میڈم۔

اب سمجھا یتی: اس کا بہت لمبٹڈ اسکوپ ہے۔ اس پر بول لیجئے۔ آئندہ بول لیجئے گا کبھی کشمیر پر۔

شری محمد خلیل الرحمن: محترمہ ڈپٹی چیئرمین صاحبہ۔ میں اس بل کی مخالفت کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ اس وجہ سے کہ یہ جو بل ہے یہ جمہوریت کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ جب کسی ریاست میں

†Transliteration in Arabic Script.

کی کبھی بھی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو سلب کر کے راشٹرپتی کو دیا جائے۔ لہذا یہ ایک غلط مثال ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کشمیریوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ۵ سال سے مسلسل صدر راج قائم ہے اور وہاں اس قسم کا امتیازی سلوک نہیں کیا گیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے ساتھ اس قسم کا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے میں ہوم منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا۔ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ۱۱ بل پینڈنگ ہیں یہ کس وجہ سے پینڈنگ ہیں۔ کیا پارلیمنٹ کو جون کے پہلے ہفتے میں نہیں بلایا جا سکتا تھا اور ان بلوں کو پاس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کسی کو بھی اس میں اعتراض نہیں تھا کہ بل کو پاس نہ کیا جائے۔ عین وقت پر یہ بات لائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت نہیں ہے پاس کیجئے۔ آج ہی پاس کیجئے ورنہ ایک عجیب قسم کے حالات جموں کشمیر میں پیدا ہو جائیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہے

صدر راج قائم کیا جاتا ہے تو اس ریاست کی اسمبلی کے جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں وہ خود بخود آرٹیکل ۳۵۶ کے تحت پارلیمنٹ کو آجاتے ہیں اور جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ۔ پورے ہندوستان کے عوام کی نمائندگی۔ ہائی ایسٹ باڈی ہوتی ہے اور یہ جو نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ مختلف خیالات کے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ اس ریاست کے مسایل سے اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز اس ریاست کے مفاد میں ہو سکتی ہے اور کون سی چیز اس ریاست کے مفاد میں نہیں ہو سکتی۔ مگر ایک دفعہ جب اس پارلیمنٹ کے اختیارات کو راشٹرپتی کو دیں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ راشٹرپتی کی شخصیت پورے ہندوستان کے لئے اور ہم سب کیلئے ایک عظیم شخصیت ہے۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کے اختیارات سلب کر لیا جائے اور وہ اختیارات راشٹرپتی کو صرف ایک شخص کو دیئے جائیں۔

اس سے غلط مثال قائم ہوگی اور آزاد ہندوستان کی تاریخ میں اس قسم

ممبر ہوں گے۔ اگر یہ بھی میڈنٹری نہیں ہے۔ یہ بھی راشٹرپتی کے ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر راشٹرپتی مناسب سمجھیں تو اس کمیٹی سے کنسلٹ کریں گے اگر مناسب نہ سمجھیں تو کنسلٹ بھی نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ۔

"Provided that before enacting any such Act, the President sholl whenever he considers it practicable to do so,..."

یہ لفظ ڈلیٹ کر دیئے جائیں اور اس کو اس طرح سے پڑھا جائے۔

"Provided that before enacting any such Act, the President shall consult a Committee constituted for the purpose consisting of 10 members of the House of the People nominated by the Speaker and five Members of the Council of States nominated by the Chairman."

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: اسٹیٹمنٹ پر ہی سن لیجئے۔ ابرار صاحب آپ اتنا ایجی ٹیٹ مت ہوئیے۔

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: First of all, I welcome this Bill because it is another assertion of the fact that we, in India, regard Kashmir as an integral and inalienable part and that we are not going to part with it under any circumstances. The increases in terrorism in Kashmir really took an acceleration from December 1989. Two events —

†Transliteration in Arabic Script.

اس کی ذمہ دار صرف آپکی حکومت ہے۔ اس سے بڑھکر میں اور کچھ نہیں کہوں گا یہ انتہائی غلط مثال ہے۔

پہلے سے ہی کشمیری عوام میں کئی قسم کے خدشات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ان کو یہ ڈر ہے آرٹیکل ۳۷۰ کے تعلق سے جیسا کہ ہمارے بی جے پی کے بھائی کہتے آرہے ہیں کہ آرٹیکل ۳۷۰ کو ختم کر دیا جائے۔ آرٹیکل ۳۷۰ تلوار کی طرح ان کی گردنوں پر لٹک رہا ہے۔ اس سے خود ان لوگوں میں بڑا ڈر پیدا ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر پھر اس قسم کے امتیازی سلوک اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتماد کشمیریوں کے دلوں میں بحال نہیں ہوگا بلکہ ان کے دلوں میں خدشات پیدا ہوں گے

لہذا میں مرکزی حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے آپ اس بل کو واپس کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بل کے سیکشن ایک اور دو کے تحت آپ نے کہا ہے کہ ایک کنسلٹیو کمیٹی قائم کی جائے گی اور کنسلٹیو کمیٹی جو قائم کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی آپ نے اس میں کہا ہے کہ ۱۰ لوک سبھا کے ممبر ہوں گے اور پانچ راجیہ سبھا کے

†Transliteration in Arabic Script.

one in December 1989 and one in January 1990—in my opinion are centrally responsible for creating an impression that India's resolve to defend its Kashmir frontiers has been weakened. One was the trading of five hard-crore terrorists for the daughter of the then Home Minister. It is good that the daughter of the then Home Minister was recovered unharmed, but the deal certainly created an impression of weakening of the resolve of the Central Government. The second was, when Mr. Jagmohan was Governor, the decision not to unfurl the national flag on 26th January in Lal Chowk. Of course, on both occasions, the BJP, which makes so much noise about Kashmir, was supporting the Government.

When I was in Government, our people in Government dealing with Kashmir were distrssed, particularly for these two incidents. They said that this was what really had created the impression amongst the terrorist groups that one more show or one more dhakka and India would let Kashmir go. That impression must go. An impression must be created that no matter what the price, no mater how cosly the affair, we shall never part with Kashmir. The only part left on the Kashmir issue is when to get back the portion which is still with Pakistan. During the time Mr. Chandrashekhar was Prime Minister, the same question whether we will unfurl the national flag or not, came up. I am happy to say with the firm stand taken by Mr. Chandrasekhar we unfured the national flag without any incident. We had made it clear that when it comes to unfurling the national flag on the Republic Day, we will brook no nonsense from anybody. I think the same thing has to be made clear. Of course, the *Ekta Yatra* for unfurling the national flag was not going to increase the resolve. In fact, that helped unite the militants. *Ekta Yatra* did more for uniting the Kashmir militants than anything else that has been done in he recent past.

What has to be recognised is this. Even if Kashmir Valley has majority of Muslims, it has a holy connection with our past. Vaishno Devi, Amarnath caves, Shiva temple and the temple founded by Shankaracharya are all there. In fact, Kashmir was created, in my opinion, by Rishi Kashyap, from whom I am supposed to have descended.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): Madam, unfortunately the *rishi* is not here to defend himself.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: So it is both Hindus and Msulims...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Truly from Kashmir to Kanyakumari.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Therefore,, both Hindus and Muslims have a direct sentimental connection in Kashmir and both of us are together. What needs to be made clear, the message which needs to be made clear is (a) We will never part with Kashmir and (b) That India will remain a secular country so that all communities can live equally as brothers. These points have to be emphasised. Today's Bill, in my opinion, is a step forward in that direction. Therefore, I compliment the Government for bringing forward this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. David Ledger, would you like to speak? Do you want to say something on this Bill?

SHRI DAVID LEDGER (Assam): I will take two or three minutes. I will be brief.

SHRI DAVID LEDGER: Thank you, Madam Deputy Chairman. If I remember corectly it was Shiekh Abdullah, the Lion of Kashmir who proudly cleimed many years ago that

[Shri David Ledger]

Kashmir was the true crucible of Indian secularism where the Hindu minority lived as equal with the Muslim majority. Madam, it is a tragedy of our history that the situation is different today. In today's Kashmir, there is tension, there is violence and there is bloodshed. In today's Kashmir, there is suspicion and hatred. In today's Kashmir there is a sense of total alienation among the people. The more we think of the problem of Kashmir, the more are we reminded of the blunders which our political leaders have committed in the past. As a matter of fact, it is these blunders which have intensified the problem of Kashmir. When we talk of the mistake committeed by our political leaders, we definitely think of the series of mistakes which have been committed in Kashmir. We have seen State, Governments being dismissed. We have seen Chief Ministers being dismissed. We have seen elections being rigged. We have seen puppet Governments being thrust down the throats of the Kashmiris. We have also seen pliable Governors being appointed in that State. These series of mistakes combined to erode the faith and the cofidence of the Kashmiris, in politicians and in the political system of this country.

Madam, I would not like to take much time because there is no time. Before I conclude, I would only like to say that there are clearly two aspects of the Kashmir problem. One is political and the other is economic. While the necessity to speed up the economic development of the Valley of the Kashmir cannot be denied, it is all the more necessary to revive the political system, the political process in the Valley. When I speak of reviving the political process in the Valley, I am surely referring to holding to elections there. It must be ensured that whenever an election is held in Kashmir, all sections of Kashmiris should be able to exercise their democratic right without any fear or inducement. Before an election is held in Kashmir, it should also be ensured that a conducive atmosphere is created whereby the people, the citizens can cast their votes in a proper manner.

Madam, the present Bill seeks to confer the powers of the Legislature of the State of Jammu and Kashmir on the President of India. I believe that a situation prevails in the State today which warrants such a price of legislations. I, therefore, appeal to all Members to pass this Bill unanimously. But at the same time, Madam, I would like to remind the Government that it should not be a permanent feature and that the Government must find ways to restore these powers to the State Legislature. The holding of elections and installation of a popular Government is the only way of doing it. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to say something, Chavanji? (*Interruptions*). I will call you, Prof. Bhattacharya. He wants to reply to some points only. He is only intervening. I will call you afterwards.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam Deputy Chairperson, my esteemed colleague, Mr. Jacob, will be able to reply to all the points which hon. Members raised. But some hon. Members from this House brought to my notice the kind of misunderstanding which is being deliberately created in the minds of some of the Kashmiri people that by bringing this kind of a Bill, we are taking away the power of the Jammu and Kashmir Assembly and that Article 370 has been totally given up.

SHRI N. K. P. SALVE: At least being diluted.

SHRI S. B. CHAVAN: No. No.

SHRI N. K. P. SALVE: Not for a moment do I subscribe to that view. But even in the papers that is what is mischievously sought to be drawn.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: That is BJP disinformation.

SHRI S. B. CHAVAN: In fact, that is why I thought that I would intervene in the matter.

I would like to bring this to the notice of the hon. Member who spoke just now and asked why, after all, we should take the plea that Parliament has no time. I must say that the hon. Member should understand the distinction between the Jammu and Kashmir Constitution and our Constitution. We have to bear in mind that after the Governor's rule ceases, these enactments continue for two years and this period is going to be over on 17th of this month. If any of the hon. Members could convince me that before the 17th it was quite possible to enact legislations on all these points, I would have definitely resorted to that kind of course. But I must tell you that that is not the position. We could not do it. From 1990 onwards President's Rule was applied. The implication of the enactment will be that this power will be co-terminous with President's rule. After President's rule ceases in Jammu and Kashmir, within one year, the elected Legislature of Jammu and Kashmir will have to ratify all the enactmens which were enacted in the meanwhile. So, please do not, for God's sake, create misunderstandings and give a totally wrong kind of message as if we are trying to do something very unusual. In fact, just to protect any legislation which was enacted during Governor's rule and thereafter by the Governor under President's rule was thought that it should be co-terminous with President's rule and thereafter it should be ratified. I do not think that by bringing this Bill, we are taking away the powers of the Jammu and Kashmir Legislature; nor are we giving up anything contained in Article 370. I thought that it was necessary on my part to clarify this position and that is why I intervened. Thank you. Madam.

SHRI MUFTI MOHD. SAYEED: Madam, I want to seek one clarification. As the Home Minister has rightly pointed out, these laws were enacted during Governor's rule. Can you not make an exception that only those laws passed during Governor's rule will be submitted to the President for his approval? Otherwise, all the laws which are to be enacted afresh will come before Parliament. You can make this exception and things will be clear.

SHRI S. B. CHAVAN: All the Bills which have been passed are proposed to be enacted in this manner and hereafter, if the President were to enact any Bill. The Committee is going to be constituted and in consultation with that Committee, the Bill will be passed if it becomes absolutely necessary. I can assure you that unless it becomes so essential that it is almost impossible to carry on the administration in a particular situaton, whch may or may not be created, we will not resort to it, It depends on the situation that will be created there. We are just taking the piwer for the President to enact such a legislation if a contingency were to arise. (*Interruptions*).

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): Madam, the hon. Minister just said that if a special situation arises, he would bypass the Parliament. This is a highly dangerous postulate not only in the context of Kashmir but in the context of the nation. Kindly make sure that you do n ot pass any law from now onwards at least without coming to Parliament. Can we get this assurance?

SHRI S. B. CHAVAN: I don't think that we propose to do any such thing. The Committee is constituted only for this purpose. The Committee is

[Shri S. B. Chavan]

consulted before any Bill is brought before Parliament. First, the Committee will be consulted and thereafter it will come to Parliament.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Saurin Bhattacharya. Final answer is goin to be given by the Minister.

SHRI MUFTI MOHD. SAYEED: Madam, the Home Minister has to make it abundant clear that only those laws whose validity has expired or is going to expire may be referred to the President of India. Any future law which is to be enacted must be referred to Parliament. He should make it clear. There is no problem.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Madam, one point for my rising is that after your new incarnation, this would be my first occasion to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: How can it be so? (*Interruptions*) That actually makes me laugh.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Madam, I feel that many issues which have been raised in the Annexure to this Bill regarding the history of Kashmir, regarding the present situation in Kashmir, regarding the future of Kashmir, perhaps, in a way, may be said to be redundant because what is really proposes to do is something unprecedented. So far as I can remember, never before was Parliament's legislative power handed over to the President in this manner. The President has inherent legislative powers to make Ordinances in the intervening period when Parliament is not in Session. But otherwise, perhaps, this is for the first time on the plea that Parliament does not have time to legislate, the power of legislation is being handed over to President. It has been done in the case of Kashmir. It is going to be done and every speaker from the Government side has found great merit in this particular Bill where Parliament's legislative power is handed over to the President. Now, they may come forward with this provision in respect of other States also, not only Jammu and Kashmir, where article 356 is introduced, the *the same thing may be done with* the help of article 357. This is something which is to be pondered over. Again, this brings about the idea of parallel legislative powers between the President and Parliament and those who dealt with the constitu*tional aspect should perhaps* have noticed—my friend, Mr. Bhatia, is there, he is always very keen on constitutional points—that the question of separation of powers has been given a go—by in the sense that when power is vested in the President it is really vested in the Council of Ministers which their big duty. And here we are in the Legislative wing. We are being deprived of the power by the Executive wing. That is another aspect. Madam Deputy Chairman... (*Interruptions*)... I know three minutes are over. Please give me more time. The point is, it has been said that the President will consult a Committee, but no separate clause for he constitution of that Committee has been found to be provided. It is said that if the President finds it practicable, he may consult the Committee which will consist of ten Members of Lok Sabha and five Members of the Council of States. Why the Council of States will have less weightage in it is not understood. Madam, another ground of my rising before Mr. Jacob concludes is that the debate should conclude with a dissenting voice and with a demand that when Mr. Jacob replies, he should repeal the Bill.

SHRI M. M. JACOB: Madam Deputy Chairman, ...(*Interruptions*)...

AN HON. MEMBER: Please be brief.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, he can also be brief.

SHRI M. M. JACOB: I got the 'brief' already from my hon. friends sitting behind me that I must be brief. And, Madam, I shall certainly be brief now. The hon. Minister,

Mr. Chavan, has clarified some of the points. Before that, our constitutional experts, Shri Murlidhar Bhandare and Shri Madan Bhatia, have already clarified some points which Members from the other side raised. I am thankful to all the fifteen Members of the House for raising some of the issues connected with Kashmir in general. As our time is very limited, I am not going into the general issues relating to Jammu and Kashmir. Only one word that I can say about it is there is considerable improvement in the security scenario of Kashmir and the position of our country has very much improved during the past few days.

Some Members have also mentioned about the human rights aspect in Jammu and Kashmir. Of course, I am not going to say more about it except that though some human rights organisations abroad are making a lot of campaign against us, though violation of human rights is there, the fact is that whenever any atrocities committed anywhere or something like that come to notice of immediate action is also taken and that is the index to prove the sincerity and effectiveness of administration of our type which believes in democracy and human rights.

Most of the Members from the Opposition who wanted to oppose this Bill were highlighting one point as if we are taking away the power of Parliament and giving everything to somewhere else. Clause (3) of the Bill is very clear. In clause (3) of the proposed Bill a provision is made for Parliamentary control over the legislation enacted by the President: "Either House of Parliament may, by resolution passed within thirty days from the date on which the Act has been laid before it, direct any modifications to be made in the Act." Parliament has the power even to make a modification within a period of 30 days. Mr. Bhandare has also mentioned about it. So there is no usurpation of the power of Parliament and we are a supreme body and the Parliament power is, there and there is nothing to be worried about.

Another hon. Member, Shri Satya Prakash Malaviya, asked what are the Bills that are enacted. In fact, there were about 16 Bills, enactments, out of which five have been deleted and only eleven which we found essential are brought before you. And there is the time constraint. As everybody knows, day after tomorrow is the final day when these have to be re-enacted. The President will have to do it before that. We are all concerned about beginning the democratic process in Kashmir. There is no difference of opinon about it. Political dialogue has started. There is no difference of opinion about that. Political initiative has to be taken and it is being taken and there is no difference of opinion on that. The Delimitation Commission constituted by the earlier Government is still going on with its work and we do not want to create an embarrassment even to the Delimitation Commission by dropping re-enactment at this stage. The Delimitation Commission activity and the Disturbed Areas Act under which we are effectively conducting the combing operations to nab militants who are coming across this side, all these are there. These eleven Bills which are before you, for which we are asking your permission now for delegating the power to the President for re-enactment, are very essential. Since we are all concerned about the security situation existing in Kashmir and the terrorists' influx in that area, we thought it is very important and that is precisely the reason why we are bringing this Bill before you. (*Interruptions*)...I was surprised when I saw the then Home Minister, Mufti Mohd. Sayeed, standing up and opposing this Bill. I looked at Mr. Jagmohan and Mufti Mohd. Sayeed at the same time and I was amazed and amused to hear all his comments. I hope he

[Shri M. M. Jacob]

will not misunderstand the genuine necessity of these Bills to be re-enacted now for the delegation of powers. With these comments I commend the Bill for approval.

THE DEUPTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Jammu and Kashmir to make laws, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes ... 81
Noes ... 50

"AYES"—81

Abrar Ahmed, Dr.
Ahluwalia, Shri S. S.
Alva, Shrimati Margaret
Azad, Shri Ghulam Nabi
Balbir Singh, Shri
Barongapa, Shri Sushil
Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
Chaturvedi, Shri Bhuvnesh
Chavan, Shri S. B.
Chowdhry, Harj Singh
Dard, Shri Jagir Singh
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.
Dronamraju, Shri Satyanarayana
Faguni Ram, Dr.
Fernendes, Shri John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal
Ghufran Azam, Shri
Hanumanthappa, Shri H.
Hariprasad, Shri B. K.
Hashmi, Shri Shamim
Hiphei, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jacob, Shri M. M.
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao
Jagmohan, Shri
Jayadevappa, Shri K. R.
Jichkar, Dr. Shrikant Ramchandra
Jogi, Shri Ajit P. K.
Kailashpati, Shrimati
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalyan, Shri Mohinder Singh
Korwar, Shri Gundappa
Ledger, Shri David
Lenka, Shri Kanhu Charan
Majumdar, Shri Sudhir Ranjan
Mani, Shri S. Muthu
Manmohan Singh, Shri
Matang Sing, Shri
Meena, Shri Moolchand
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Narayanasamy, Shri V.
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Pachouri, Shri Suresh
Parmar, Shri Rajubhai A.
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shri Shivajirao Giridhar
Pragada Kotaiah, Shri
Rafique Alam, Shri
Ramachandran, Shri S. K. T.
Rao, Shri V. Hanumantha
Ratan Kumari, Shrimati
Rathwa, Shri Ramsinh
Razi, Shri Syed Sibtey
Reddy, Shri G. Prathapa
Sahay, Shri Dayanand
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Salve, Shri N. K. P.
Sanadi, Prof. I. G.
Sarma, Shrimati Basanti

Satchindananda, Shri
Satya Bahin, Shrimati
Sharma, Shri Venod
Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao
Shiv Shanker, Shri P.
Singh, Shri K. N.
Singh, Shri Surender
Singh, Shri Vishvjit P.
Singla, Shri Surinder Kumar
Swamy, Shri Subramanian
Thakur, Shri Rameshwar
Verma, Shrimati Veena
Yadav, Shri Ram Gopal
Yadav, Shri Ram Naresh

"NOES"—50

Ahmad, Dr. Z. A.
Azmi, Maulana Obaidullah Khan
Baby, Shri M. A.
Balanandan, Shri E.
Basu Ray, Shri Sunil
Bhandari, Shri Ram Deo
Bhattacharya, Prof. Saurin
Ganesan, Shri Misa R.
Gautam, Shri Anand Prakash
Ghosh, Shri Dipen
Giri Prasad, Shri N.
Goswami, Shri Ramnarayan
Gujral, Shri Inder Kumar
Jaiswal, Shri Anant Ram
Kaldate, Dr. Bapu
Khan, Shri Muhammad Masood
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.
Lather, Shri Mohinder Singh
Malaviya, Shri Satya Prakash
Md. Salim, Shri
Mohammed Afzal *Alias* Meem Afzal, Shri
Mohanty, Shri Sarada
Morarka, Shri Kamal
Mukherjee, Shri Samar
Padmanabham, Shri Mentay
Pillai, Shri Ramachandran
Poddar, Dr. R. K.
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
Raju, Shri J. S.
Rao, Shri Moturu Hanumantha
Reddy, Shri S. Jaipal
Sanjaya Sinh, Dr.
Saqhy, Shri T. A. Mohammad
Sayeed, Mufti Mohd.
Sen, Shri Ashis
Sen, Shri Sukomal
Siddiqui, Shri Abdul Samad
Singh, Shri Shankar Dayal
Singh, Shri W. Kulabidhu
Sinha, Shrimati Kamla
Sinha, Shri Yashwant
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Sreedharan, Shri Arangil
Trivedi, Shri Dineshbhai
Veerappan, Shri K. K.
Venkataraman, Shri Tindivanam G.
Viduthalai Virumbi, Shri S.
Vizol, Shri
Yadav, Shri Ish Dutt
Yadav, Shri Ranjan Prasad

6.00 P.M.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shri Krishan Lal Sharma and Shri Jagdish Prasad Mathur.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Both are absent.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, it is not moved.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jacob.

SHRI M. M. JACOB: Madam, I move:

"That the bill be passed".

The question was proposed.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Madam, I want to speak on the third reading of the Bill... (*Interruptions*)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Could you a little brief? We have so many statements... (*Interruptions*)...

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Madam, with your permission once again I raise may voice of protest against this very serious lapse on the part of the Government which is trying to compound parliamentary democracy in this country. The Minister, despite our request again and again, has refused to give us any assurance that in future he will not continue the some practice so far as Jammu & Kashmir is concerned. What is the problem with Jammu and Kashmir? Every dimension has been explored. But one dimension which you must know is that the people of Jammu & Kashmir say that their voice is not heard. This is the only forum where their voice can presently be heard whenever a Bill is brought here. The hon. Minister tells us that because of expediency and other things he wants this to be condoned. All right. Even if we condone past, he does not give us any assurace for the future. We have seen in this House and elsewhere dark days of democracy also and those dark days remind us that once you start compromising with this, step by step the danger ahead is full of pitfalls. Therefore, with all force I request and suggest to all my friends here, please see the danger and do not compromise with chastity of the Parliament. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

SHRI DIPEN GHOSH: Madam (Interruptions...mayn

terruptions)... may I ask a clarification... (Inerruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have already said the, "Ayes have it." ...(*Interruptions*)... You should have risen before I said, "the Ayes have it" ...(*Interruptions*)... You should have asked for a division before that. O ce I say the Bill is passed, you hove already crossed the bridge, you have crossed the river. You cannot go bac ...(*Interruptions*)...

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): But he did say, 'the Noes have it'...(Interruptions)...

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Madam, we did say...(Interruptions)... The Deputy Chairman: Let me explain for the benefit of new Members...(Interruptions)... Perhaps, the new Members should know this...(Interruptions).. When I say, "the Ayes have it", I always give a pause ...(Interruptions)... At that point you should immediately say, "division". (Interruptions).

THE DIPEN GHOSH: I said it ...(*Interruptions*)...

SHRI S. JAIPAL REDDY: We said it. It is our misfortune that the Chair did not note it. It was said from this side....(Interruptions)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know, "the Ayes have it"... (*Interruptions*)... Now, don't put the blame on me...(*Interruptions*)... Just a second...(*Interruptions*)... it is not the first time. Even while I was passing the clauses you were saying, "the Noes have it" and you did not ask for a "division" when I said. "the Ayes have it." You said, "the Noes have it" ...(*Interruptions*)... I did not hear you say. "division". After I say the Bill is passed you said, "division"...(Inerruptions)... Don't put the blame on the Chair for your failure. You have seen the result of the division. The result is clear...(*Interruptions*)...

Just a minute...(*Interruptions*)... Jagesbhai, just a minute, please.... ...(*Interruptions*)... Please keep quite...(*Interruptions*)... The result of the division is before me. I have just announced the result of the division and the result of the division is before me. Don't put the blame on the Chair. Don't put it that I passed the Bill without division...(*Interruptions*) Don't blame the Chair...((*Interruptions*)...

SHRI DIPEN GHOSH: I am true to my conscience. I said that I wanted a division.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I won't agree to it...(*Interruptions*)...

SHRI S. JAIPAL REDDY: What is the great disadvantage in going through with it again?...(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just now we had a division. I can read it out...(*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: So what? Every time we want it, we can ask for it...(*Interruptions*) It was at the consideration stage.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have no objection. I would never have any objection to have a division whether it goes in favour of Noes or Ayes. It doesn't concern me whether you get it or they get it, while I am in the Chair. We have just had a division and it said 81-50...(*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: That was a the consideration stage. When this Bill was commended for passing, we wanted a divsion...(*Interruptions*)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया (बिहार) : संसदीय परंपरा के प्रति इतने ही सजग हैं तो पहले क्यों नहीं उठते ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is very unfortunate...(*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: It is very unfortunate for all of us.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is very unfortunate for you that you are not mustering enough support. You are putting the blame on the Chair...(*Interruptions*) It is very unfortunate and everybody has seen the result...(*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: We are not putting the blame on the Chair...(*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: We are not putting the blame on the Chair...(*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD AFZAL alias MEEM AFZAL (Uttar Pradesh): This is wrong. We did not put the blame on the Chair...(*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: Don't conclude that. We are asserting our right...(*Interruptions*)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : महोदया, संसदीय परम्परा के प्रति अगर इतने सजग हैं तो इन्हें तुरंत उठकर बोलना चाहिए था, वोटिंग की मांग करनी चाहिए थी। उस समय क्या सो रहे थे ? अब जबकि बिल पास हो गया है तो एक नई परम्परा शुरू करना चाहते है।

SHRI DIPEN GHOSH: We have got every right. We are not putting the blame on the Chair...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Bill has already been passed. They cannot raise the issue now ...(*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: The Chair may not have heard it. Our people pressed for a division. But we are not blaming the Chair at all. You are under a wrong impression. Let me put it on record that we did not blame the Chair in any sense at all ...(*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: Don't make any hasty conclusion. We are not blaming the Chair. You may not have heard us...(*Interruptions*) We are asserting our rights.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You know that in the past also once I did not hear it because you did't ask for it or some Members didn't ask for it in time. There is always a time for asking for a division. You cannot ask for a division when I say "The Bill is passed". You cannot get up any moment and say "We want a division". There is always a time. I have the result of the division before me... (*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Gujral said something about darkar days of the democracy. What did he mean?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Forget it.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Madam, it is already 6 o'clock. It is better if the statement is made tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will take the sense of the House. We have one statement which was slated for 5.30 p.m. which Mr. Jacob was to make on Bhilai and we have... (*Interruptions*) पूरी बात तो सुन लीजिए यही तो खराबी है । मैं कल से यही बात कह रही हूं । मेरी बात सुनते नहीं हैं इतना शोर होता है कि मुझे सुनायी नहीं देता । कृपया सुन लिया कीजिए फिर मन में आए तो बोलिए ।

This statement is there and there are clarifications to be sought on the Railway Minister's statement. Now what do you want?

HON. MEMBERS: It can be taken up tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Both? Okay, this is the sense of the House. The House is adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at ten minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 16th July, 1992.